सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHI/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023
www.newsparivahan.com
परिवहन विशेष
वर्ष 03, अंक 198, नई दिल्ली, गुरुवार 25 सितंबर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार
मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता.

03 देश का अल्पसंख्यक व्यापारी भी कर रहा है मोदी जी का धन्यवाद : अनीश अब्बासी
06 अंग्रेजी आवश्यक है
08 अब मतदाता सोशल मीडिया के ज़रिए ले सकेंगे चुनाव विभाग से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी

दिल्ली में ई रिक्शा निर्माताओं द्वारा निर्मित एवं बिक्री के लिए उपलब्ध वाहन प्राप्त राज्य टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट के अनुसार नहीं, कौन है जिम्मेदार ?

संजय बाटला

आपकी जानकारी के लिए बता दें टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट एक प्रकार से अनुमोदन एक प्रमाणन योजना है जिसका उद्देश्य विचाराधीन उत्पाद के बारे में क्रेता का विश्वास बढ़ाना और यह आश्वासन देना है कि उत्पाद दस्तावेज समीक्षा, डिजाइन और प्रमाणन की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों/कोड/कन्वेंशन और/या आईआरएस नियमों के अनुरूप है।

दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध ई रिक्शे, ई लोडर और नियम के अनुसार पंजीकरण नही होने वाले दो पहिया सवारी वाहन भारत सरकार द्वारा अधिकृत जांच एजेंसियों द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र और दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टेट अप्रूवल/टाईप अप्रूवल सर्टिफिकेट के आधार पर निर्मित नही है और उसके बाद भी दिल्ली परिवहन विभाग की पंजीकरण शाखाएं बेखौफ होकर ऐसे वाहनों को पंजीकृत कर दिल्ली कि सड़को पर चल रही जनता का जीवन असुरक्षित करने में सलग्न है। दिल्ली की सड़को पर परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों के निजी स्वार्थ के कारण इस प्रकार के वाहनों के सड़को पर आने से होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा, क्या परिवहन विभाग ? अवैध बदलावों के कारण से ई-रिक्शा, ई लोडर हो रहा हैं असुरक्षित।

भारत में ई-रिक्शा ने पिछले एक दशक में सस्ते और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के तौर पर अपनी जगह बना ली है। लाखों परिवारों की रोजी-रोटी भी इस पर निर्भर है। शहरों और कस्बों में छोटे सफ़र के लिए यह सबसे आसान और सस्ता विकल्प बन चुका है। यही वजह है कि ई-रिक्शा इंडस्ट्री को हरित क्रांति और शहरी गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है।

इलेक्ट्रिक निर्माता नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। नतीजा यह कि सुरक्षा, भरोसा और इंडस्ट्री का भविष्य तीनों गहरी चोट खा रहे हैं। हाल के दिनों में इस इंडस्ट्री ने जिस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया है, वह चिंताजनक है। निर्माताओं और वाहन मालिकों के बीच एक नया ट्रेंड तेज़ी से फैल रहा है। ई-रिक्शा में पीछे अतिरिक्त सीट लगाकर यात्रियों और सामान दोनों को साथ ले जाने की सुविधा दी जा रही है। नियम स्पष्ट कहते हैं सवारी ई-रिक्शा केवल चार यात्रियों और एक चालक के लिए मान्य है, जबकि कार्गो / लोडर ई-रिक्शा केवल सामान ढुलाई के लिए रजिस्टर्ड होता है। इसके बावजूद अतिरिक्त सीट लगाकर इन नियमों को तोड़ा जा रहा है। मोटर वाहन नियम के अनुसार परिवहन विभाग की स्वीकृति के बिना किसी भी तरह का डिज़ाइन या सीटिंग बदलाव गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आता है। यह प्रवृत्ति न केवल क़ानून की अनदेखी है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज़ से भी खतरनाक साबित हो रही है। अतिरिक्त भार डालने से वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम उतना असरदार नहीं रहता और बैटरी व मोटर पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऐसे हालात में दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में आ रही हैं।

देखने में आ रहा है सिर्फ ई-रिक्शा ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में भी कई निर्माता ग़लत रास्ता अपना रहे हैं। मानक के अनुसार लो-स्पीड ई-दोपहिया केवल 250 वॉट मोटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार तक ही मान्य हैं। इन वाहनों के लिए न तो लाइसेंस की ज़रूरत होती है और न ही रजिस्ट्रेशन, लेकिन हक़ीक़त यह है कि बाज़ार में कई कंपनियाँ 250 वॉट से ज़्यादा क्षमता वाली मोटर लगाकर इन्हें ₹लो-स्पीडर₹ के नाम से ही बाज़ार में बेच रहे हैं। नतीजा सड़क पर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हेलमेट तेज़ रफ़्तार वाले दोपहिया दौड़ रहे हैं, जो दुर्घटनाओं को दावत देने के बराबर है।

इस प्रवृत्ति का असर पूरे बाज़ार पर है, नियमों का पालन करने वाले संगठित निर्माता इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि अवैध मॉडल बाज़ार में सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। कुछ निर्माताओं के अल्पकालिक लाभ के लालच में इंडस्ट्री के वह निर्माता जो नियमों का पालन करते हुए वाहन निर्माण कर रहे हैं संकट में आ रहे है।

यहां सवाल ये उठता हैं की

1. गैर-क़ानूनी बदलाव के साथ निर्मित वाहनों पर परिवहन विभाग कार्यवाही करने की जगह उन्हें पंजीकृत किस आधार पर कर रहा है।

2. आखिर परिवहन विभाग नियमों को लागू करने के लिए कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा ?

यह बात सच है की ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक दोपहिया ने भारत में ग्रीन मोबिलिटी का सपना साकार किया है लेकिन नियम को दरकिनार कर निर्मित वाहनों को सड़को पर चलने देने और चलवाने वाले परिवहन विभाग और गलत वाहन बना कर बेचने वाले निर्माताओं के कारण सड़को पर होने वाली दुर्घटनाएं और जान माल के नुकसान की भरपाई की कीमत ग्रीन मोबिलिटी के नाम से नही हो सकती।

ग्राहकों को भी जागरूक होना होगा और याद रखना होगा की सवारी ई रिक्शा एवम्‌ लोडर/ कार्गो ई-रिक्शा अलग-अलग श्रेणियाँ हैं और अलग अलग कार्यों के लिए है इसके अलावा लो-स्पीड ई-दोपहिया केवल 250 वॉट तक ही सुरक्षित और वैध हैं।

जनता की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग को तत्काल प्रभाव से नियमों के अनुसार वाहन ना बनाने वाले निर्माताओं उन्हें बेचने वाले वाहन डीलरो और उनके पंजीकृत करने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ प्रवर्तन शाखा दिल्ली परिवहन विभाग, यातायात पुलिस को आदेश जारी कर ऐसे वाहनों को तत्काल नियम के अनुसार धाराएं लगा कर बंद करने का आदेश जारी करने चाहिए।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

भारत में विवाह और परिवार के अधिकार: कानून और वास्तविकता

पिंकी कुंडू महासचिव टोलवा ट्रस्ट
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भाजपा

TEMPLE OF LIBERALIZATION AND WELFARE ALLIED TRUST (REGD.) TOLWA

भारत में विवाह और परिवार का अधिकार एक जटिल मुद्दा है, जो व्यक्तिगत कानूनों, सांविधिक अधिनियमों और न्यायिक व्याख्याओं का मिश्रण है। हालांकि यह अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से अनुच्छेद 21 के तहत ₹जीवन के अधिकार₹ का एक अभिन्न अंग माना गया है।

कानून : संवैधानिक व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में (जैसे लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और शाफ़िन जहाँ बनाम भारत संघ) यह माना है कि किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मौलिक हिस्सा है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास रहा है जिसने व्यक्तियों को सामाजिक दबाव और तथाकथित ऑनर किलिंग से बचाया है।

विवाह संबंधी कानून: भारत में विवाह को नियंत्रित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानून हैं, जो व्यक्ति के धर्म पर निर्भर करते हैं। इनमें हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम शामिल हैं। अंतर-धार्मिक या अंतर-जातीय जोड़ों के लिए, विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 विवाह के लिए एक धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

आनंद विवाह अधिनियम: एक हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्यों को आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है, जो समुदाय की एक अलग कानून की लंबे समय से चली आ रही मांग थी।

वर्तमान विवाद और वास्तविकता

कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण विवाद हैं, खासकर LGBTQ+ व्यक्तियों के अधिकारों और मौजूदा कानूनों की सीमाओं के संबंध में।

समलैंगिक विवाह: यह विवाद का एक प्रमुख क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अक्टूबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि संविधान के तहत विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संसद का काम है, न कि न्यायपालिका का।

लिव-इन संबंध: हालांकि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि क्वीयर व्यक्तियों को बिना किसी धमकी या जबरदस्ती के सहवास करने और ₹एकजुट होने₹ का अधिकार है। कुछ राज्यों में अदालतों ने भी फैसला सुनाया है कि समलैंगिक जोड़ों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप गैरकानूनी नहीं हैं और कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं।

वास्तविकता से अलगाव: यह कानूनी वास्तविकता और LGBTQ+ समुदाय की आकांक्षाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है। 2018 में समलैंगिक गतिविधि को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन विवाह न कर पाने से समलैंगिक जोड़ों को विरासत, संयुक्त संपत्ति और गोद लेने के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों और लाभों से वंचित होना पड़ता है।

अन्य विवाद: विवाह योग्य आयु में असमानता: पुरुषों (21) और महिलाओं (18) के लिए अलग-अलग विवाह योग्य आयु को भेदभावपूर्ण बताया गया है। हालांकि सरकार ने महिलाओं की आयु बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन विधेयक अभी भी संसदीय समिति के विचाराधीन है।

विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग ₹विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने₹ के आधार पर तलाक देने के लिए किया है, जो तलाक कानूनों के पारंपरिक ₹दोष सिद्धांत₹ से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

पड़ोसी देशों में स्थिति

भारत के पड़ोसी देशों में LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए विवाह के अधिकार की कानूनी और सामाजिक स्थिति काफी भिन्न है।

नेपाल: नेपाल LGBTQ+ अधिकारों के लिए दक्षिण एशिया में एक अग्रणी देश है। जून 2023 में, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह के अस्थायी पंजीकरण की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया, और नवंबर 2023 में, एक समलैंगिक जोड़ा कानूनी रूप से अपनी शादी पंजीकृत कराने वाला पहला जोड़ा बन गया।

पाकिस्तान: पाकिस्तान में समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता है, और समलैंगिक विवाह या नागरिक यूनियनों के लिए कोई कानूनी मान्यता नहीं है।

बांग्लादेश: समलैंगिक यौन गतिविधि को अपराध माना जाता है, और समलैंगिक संबंधों के लिए कोई कानूनी सुरक्षा या मान्यता नहीं है।

श्रीलंका: हालांकि समलैंगिक यौन गतिविधि को अपराध मानने वाला कानून अभी भी किताबों में है, लेकिन इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला एक हालिया विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया है। हालांकि, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है।

चीन: मुख्य भूमि चीन में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है।

भूटान: 2021 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन समलैंगिक विवाह को कोई कानूनी मान्यता नहीं है।

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत
tolwaindia@gmail.com

रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव

स्टॉल प्रस्ताव :
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण :
रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें : 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ :
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें :
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क : इंदु राजपूत
मोबाइल : 9210210071

विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
• दशहरे के दूसरे दिन
• दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
• स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड
स्थान विवरण :
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली
संपर्क सूत्र : इंदु राजपूत, मोबाइल : 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

"श्री श्री दुर्गा शरणम" तैंतीसवां सार्वजनिक दुर्गोत्सव

प्रिय महोदय,

आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके शहर उत्तम नगर में 'उत्तम नगर कालीबाड़ी द्वारा शनिवार दिनांक 27 सितंबर, 2025 से 2 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार तक सी-50, मनसा राम पार्क, नई दिल्ली-59 में श्री श्री दुर्गा माँ की पूजा एवम्‌ 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार श्री श्री काली माँ की पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सबसे हार्दिक निवेदन है कि आप सब इस विशाल आयोजन में सम्मिलित होकर माँ दुर्गा एवम्‌ काली माँ का आर्शीवाद प्राप्त करें और इस आयोजन को सफल बनायें।

प्रिय भक्तों!

हमें आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तम नगर कालीबाड़ी, सी-50, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में 33वें वर्ष दुर्गा पूजा एवं काली पूजा समारोह का आयोजन कर रही है। हम आपके परिवार और मित्रों को 27 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक हमारे काली मंदिर में आयोजित होने वाले इस समारोह में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं।

आइए एक बार फिर खुशियाँ बाँटें, अपनी आत्मा को समृद्ध करें और पारिवारिक माहौल में त्योहार का आनंद लें। आप सभी के उदार सहयोग और भागीदारी की हम बहुत सराहना करते हैं। दुर्गा पूजा पर और हमेशा आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।

भवदीय
उत्तम नगर कालीबाड़ी,
मलय डे (अध्यक्ष) 7217666618

जयंत डे (सचिव) 9654385888
पिंकी कुंडू (सदस्य)

पूजा कार्यक्रम-2025
27 सितंबर 2025, (शनिवार). बोधन
28 सितंबर 2025, (रविवार) षष्ठी आमंत्रण और अधिबास
29 सितंबर 2025, (सोमवार) सप्तमी पूजा
30 सितंबर 2025, (मंगलवार) अष्टमी और संधि पूजा
1 अक्टूबर 2025, (बुधवार) नवमी पूजा
2 अक्टूबर 2025, (गुरुवार) दशमी पूजा और विसर्जन
पुष्पांजलि 11.00 बजे से 1:00 बजे तक,
प्रसाद वितरण 1.00 बजे से 1:30 बजे तक,
भोग वितरण 1.30 बजे से 3.00 बजे तक।
संध्या आरती- 7.00 बजे
श्री श्री काली पूजा सोमवार, 20 अक्टूबर, 2025

कार्यक्रम का स्थान:
कालीबाड़ी, सी-50, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

You're Invited!
Anandomela Food Fiesta 2025
Celebrate the spirit of Durga Puja with food, fun, and festivity!

Join us at our much-awaited Anandomela Food Fiesta, where the aroma of tradition meets the joy of celebration! Bring your favorite homemade delicacies, share your culinary skills, and enjoy a vibrant evening with your community.

Date: 28.09.2025
Venue: KALI BARI (uttam nagar)
Time: 7.00PM

Whether you're a seasoned cook or just love feeding people, we welcome your participation with open arms!

For stall bookings and participation details,
Please contact:
Mrs.Pinki Kundu- 7053533169
Mrs.Tithi Ghosh- 9013088489

Let's make this Durga Puja even more delicious and memorable!

Regards
Jayant Dey
General Secretary

श्रीगणेश जी के आध्यात्मिक रहस्य

भारत देश की सभ्यता संस्कृति का त्यौहार एक अभिन्न अंग है। त्यौहार हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियां, उमंग उत्साह लेकर आते हैं इन्हीं त्यौहारों में से एक त्यौहार गणेश चतुर्थी है।

गणेश जी के पूरे शरीर से सिर को अलग कर के देखेंगे तो मनुष्य का ही शरीर दिखता है परंतु इस शरीर को हाथी का चेहरा दिया गया है इसीलिए उन्हें गजधर कहते हैं जिनमें हाथी के समान अंग दिखाई दिए हैं। आंख, कान, सूंड, दांत आदि। परंतु इन सभी के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है वह इस प्रकार है।

सूंड

सूंड आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है। हाथी की सूंड इतनी मजबूत और शक्तिशाली होती है कि वह वृक्ष को भी उखाड़ कर, सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लेता है। गोया वह एक बुलडोजर और क्रेन दोनों का कार्य एक साथ कर सकता है। साथ ही छोटे-छोटे बच्चों को भी प्रणाम करता है, किसी को पुष्प अर्पित करता है, पानी का लोटा चढ़ाकर पूजा करता है, सुई जैसी सुक्ष्म चीज को भी उठा लेता है। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने मूल आदतों को जड़ों से उखाड़कर फेंकने में समर्थ होता है। सुक्ष्म से सुक्ष्म बातों को भी धारण करने के लिए, दूसरों को सम्मान, स्नेह और आदर देने में वह कुशल होता है। अपने पुराने संस्कारों को जड़ से पकड़कर निकाल फेंकने के लिए भी हाथी की सूंड जैसी उसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। इस तरह हाथी की सूंड ज्ञानी व्यक्तियों की क्षमताओं का प्रतीक हैं।

कर्ण(कान)

उनके कान पंखे जैसे बड़े बड़े होते हैं बड़े-बड़े खुले कान हमें यह शिक्षा देते हैं कि आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बात चाहे वह स्व के प्रति हो या अन्य के प्रति से ध्यान से सुने। कान को मुख्य ज्ञानेंद्रिय माना गया है। गुरु भी जब अपने शिष्य को मंत्र देते हैं तो उसके कान में ही उच्चारण करते हैं। भगवान ने जब गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कानों के द्वारा ही उसे सुना। अतः बड़े-बड़े कान, ज्ञान श्रवण के प्रतीक हैं। वे ध्यान से, जिज्ञासापूर्वक, ग्रहण करने की भावनाओं को भावना से, पूरा चित्त देकर सुनने के प्रतीक हैं। ज्ञान की साधना में श्रवण, मनन और निज अध्ययन यह तीन पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें सबसे प्रथम श्रवण है। ज्ञान के सागर परमात्मा के विस्तृत ज्ञान का श्रवण इन बड़े कानों से समुचित करना ही इसका प्रतीक है।

आंखें

उनकी आंखे दिव्य दृष्टि वाली होती है उसे छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। यदि उसे छोटी चीज भी दिखाई नहीं देती तो वह सबको अपने पांव के नीचे रौंदता चला जाता। दूसरा उनकी आंखें छोटी लेकिन दूरदर्शिता का प्रतीक होती हैं। हमारे जीवन में कई सुक्ष्म बातें, रहस्यपूर्ण बातें होती हैं जिन्हें दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, उनके परिणाम को देखते हुए, फिर अपनानी चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति का भी एक गुण होता है। वह छोटो में भी बढ़ाई देखता है। हर एक की महानता उसके सामने उभरकर आती है और सब का सब को आदर देता है उसके मन को अपने शब्दों से रौधता नहीं है।

महोदर

बोलचाल की भाषा में यह कहा जाता है कि इसका तो पेट बड़ा है इनको कोई भी बात सुना दी जाए तो वह बाहर नहीं निकलती हैं। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा होता है। जो कि समाने की शक्ति का प्रतीक है। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने भी निंदा स्तुति, जय-पराजय ऊंच-नीच की परिस्थितियां आती है परंतु वह उनको स्वयं में संभाल लेता है। गणेश जी का लंबा पेट अथवा बड़ा पेट (महोदर) ज्ञानवान के इसी गुणों का प्रतीक है।

गणेश जी की चार भुजाएं दिखाई जाती है उनमें से एक में कुल्हाड़ा दिखाया जाता है। कुल्हाड़ा तो काटने का एक साधन है ज्ञानवान व्यक्ति मे ममता के बंधन काटने और संस्कारों को जड़ से उखाड़ने की क्षमता होती है उसी का प्रतीक यह कुल्हाड़ा है। ज्ञान एक कुल्हाड़ी की तरह से है जो उसके मन के जुड़े हुए दैहिक नातो को चूर चूर कर देता है। गीता में भी ज्ञान को तेज तलवार की उपमा दी गई है जिससे कि काम रूपी शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। आसुरी संस्कारों को मार मिटाने के लिए ज्ञानरूपी कुल्हाड़ा जिसके पास है वह आध्यात्मिक योद्धा ही ज्ञानी है। हमें गणेश जी जैसा पूजनीय बनना है तो हमें भी ऐसी बड़ी शक्तियां धारण करनी होगी।

वरद्(मुद्रा)

गणपति जी का एक हाथ सदा वरद मुद्रा में दिखाया जाता है। देवता हमेशा देने वाले ही होते हैं। जिसकी जैसी भावना, श्रद्धा होती है उन्हें वैसी ही प्राप्ति अल्पकाल के लिए होती है। वरद मुद्रा इस बात का प्रतीक है। जैसे गणेश जी हमेशा दाता के रूप रहते हैं वैसे ही ज्ञानवान व्यक्ति की स्थिति ऐसी महान हो जाती है कि वह दूसरों को निर्भयता और शांति का वरदान देने की सामर्थ वाला हो जाता है। वह अपनी शुभ मनसा से दूसरों को आशीष प्रदान कर सकता है।

बंधन(रस्सी)

आत्मा का परमात्मा के साथ नाता जोड़ना भी प्रेम के बंधन में बँधना है। गणपति जी के एक हाथ में जो डोरे (बंधन) हैं वह इसी प्रेम के डोरे हैं। वे दिव्य नियमों के शुद्ध बंधन है। ज्ञानी स्वयं इन नियमों के बंधनों में स्वयं को ढालता है।

इसका दूसरा भाव है कि आत्मा परमधाम से अकेली आती है जैसे ही वह देह में प्रवेश करती हैं तो कई संबंधों के बंधनो में बंध जाती है और उनके साथ उसका कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। ऐसे कई बंधनों में बंधती चली जाती है। इसमें सुख के बंधन कम और दुख के बंधन अधिक होते हैं। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए ही आत्मा ईश्वर के पास आती है कि मुक्तिदाता मुझे मुक्त करो।

मोदक

मोदक शब्द खुशी प्रदान करने वाली वस्तु का वाचक है। लड्डू बनाने के लिए चनों को पीसना, भीगाना, भूनना पड़ता है तब कहीं जाकर वह प्रिय पदार्थ बनता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति को भी अनेक कठिनाइयों, संकटों, दुश्वारियों इत्यादि में से गुजरना पड़ता है अर्थात उसे तपस्या करनी पड़ती है। जीते जी मरना होता है और इसी से वह अधिकाधिक मिठास व ज्ञान का रस अपने आप में भरता है। तब वह स्वयं भी सदा खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी प्रदान करता है। इस प्रकार हाथ में मोदक का होना ज्ञान निष्ठा, ज्ञान रस से सराबोर स्थिति का प्रतीक है।

इसका दूसरा भाव यह है कि हम हमेशा मुख से मीठा बोले, कड़वा न बोले हर एक को सुख पहुंचाये, ऐसे बोल बोले कि किसी का मान सम्मान और बढ़े।

गणपति जी के अलंकारों व प्रतीको का उल्लेख किया गया है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गणपति जी, परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान को गहराई से समझने वाले, उसे जीवन में पूर्णता व्यवहार में लाने वाले, स्वयं लक्ष्य स्वरूप और ज्ञान की शक्तियों को प्राप्त करने वाले ही का प्रतीक है।

गणपति अथवा गणनायक एक प्रकार से प्रजापति अथवा प्रजापिता शब्द का पर्यायवाची है क्योंकि गण और प्रजा लगभग समानार्थक हैं। अतः कहा जा सकता है कि गणपति प्रजापिता ब्रह्मा ही थे यह उनका कर्तव्य वाचक नाम है क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने ही परम पिता परमात्मा शिव से ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञानियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और परमपिता परमात्मा शिव ने उनके पुराने संस्कारों के स्थान पर नए संस्कार और दिव्य बुद्धि प्रदान की। उन्होंने ईश्वरीय बुद्धि के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में आए विघ्नों को पार किया इसीलिए वे विघ्न विनाशक भी हैं।

शास्त्रों में परमात्मा के तीन स्वरुप सत, चित और आनन्द बताये गये हैं...

सत प्रगट रुप से सर्वत्र है चित मौन तथा आनन्द अप्रगट है, जड़ वस्तुओं में सत तथा चित है परन्तु आनन्द नहीं है जीव में सत और चित प्रगटता है परन्तु आनन्द अप्रगट रहता है अर्थात अप्रगट रुप से रहता है, अव्यक्त रुप से है वैसे आनन्द अपने ही अन्दर है फिर भी आनन्द को हम बाहर खोजते हैं, हम नारी देह, धन संपत्ति आदि में आनन्द खोजते हैं, किन्तु आनन्द तो हमारे अन्दर ही है। जैसे दूध में मक्खन रहता है फिर भी दिखायी नहीं देता किन्तु दूध से दही बनाकर मंथन करने पर मक्खन दिखायी पड़ता है ठीक वैसे ही हमें भी मनोमंथन करके आनन्द को प्रकट करना है।

जीव है तो ईश्वर का ही तो भी ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता, इसी कारण आनन्द नहीं मिलता। आनन्द के दो रुप हैं - साधन जन्य एवं स्वयंसिद्ध, साधन जन्य आनन्द अर्थात विषय जन्य आनन्द, जो साधन या विषय के नाश होने पर उस आनन्द का भी नाश होता है और होगा, योंगियो के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता फिर भी उनको आनन्द है अर्थात सदा आनन्द से रहते हैं, इससे सिद्ध होता है आनन्द अन्दर ही है।

सत चित आनन्द ईश्वर में परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण सतरुप, परिपूर्ण चितरुप, परिपूर्ण आनन्द रुप हैं।

परमात्मा श्रीकृष्ण परिपूर्ण आनन्द स्वरुप हैं, बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है, ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद् अंश है फिर भी परिपूर्ण नहीं है, जीव को यदि आनन्द रुप होना हो तो उसे सच्चिदानन्द आश्रित होना है, जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती, आनन्द नहीं मिलता है, संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं हैं, जीव जब ईश्वर से मिलता है तभी वह परिपूर्ण होता है।

गणेश जी के 12 नाम

1.सुमुखः सुन्दर मुख वाले
2.एकदंतः एक दांत वाले
3.कपिलः कपिल वर्ण वाले या भूरे रंग के
4.गजकर्णकः हाथी के कान वाले
5.लंबोदरः लम्बे पेट वाले
6.विकटः विपत्ति को नाश करने वाले
7.विघ्न-नाशः विघ्नों (बाधाओं) को दूर करने वाले
8.विनायकः न्याय करने वाले या सभी के नेता
9.धूम्रकेतुः धुएँ के रंग वाले या धूम्रवर्ण वाले
10.गणाध्यक्षः गणों के अध्यक्ष
11.भालचंद्रः मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले
12.गजाननः हाथी के मुख वाले

इन नामों के लाभ

इन नामों का स्मरण करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं.

विद्यार्थियों के लिए इनका जप करना विशेष लाभकारी माना जाता है, जिससे उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है.

गणेश जी के इन 12 नामों का जाप करने से व्यक्ति को धन, पुत्र और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है.

किसी भी शुभ कार्य, जैसे यात्रा, रोजगार या विवाह के शुभारंभ के समय इन नामों का उच्चारण करने से कार्य की अड़चनें दूर होती हैं.

जिंदगी जो शेष है वो विशेष हे

मैहर देवी का मंदिर: यहाँ आज भी आते हैं आल्हा और उदल

कहते हैं मां हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती हैं। उत्तर में जैसे लोग मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए वैष्णो देवी तक पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी 1063 सीढ़ियां लांघ कर माता के दर्शन करने जाते हैं।

सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मैहर का मतलब है मां का हार। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है।

पर्वत की चोटी के मध्य में ही शारदा माता का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरवी, भगवान, हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेष नाग, फूलमति माता, ब्रह्म देव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है।

आल्हा और उदल करते है सबसे पहले माँ के दर्शन क्षेत्रीय लोगों के अनुसार अल्हा और उदल जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, वे भी शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे।

इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया था। आल्हा माता को शारदा माई कह कर पुकारा करता था। तभी से ये मंदिर भी माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे।

क्या है मंदिर से जुड़ी कहानी- माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी।

वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी ज़िद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी-देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जान-बूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया।

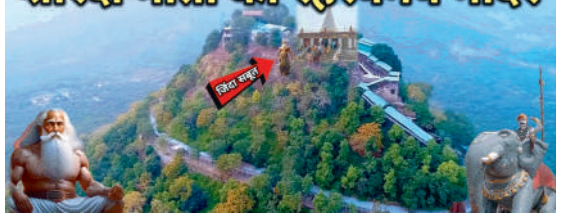

यज्ञ-स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ-अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला, तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया।

उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे।

ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहां भी सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिवजी को फिर से पति रूप में प्राप्त किया।

माना जाता है कि यहां मां का हार गिरा था। हालांकि, सतना का मैहर मंदिर शक्ति पीठ नहीं है। फिर भी लोगों की आस्था इतनी अडिग है कि यहां सालों से माता के दर्शन के लिए भक्तों का रेला लगा रहता है।

इसके अलावा, ये भी मान्यता है कि यहां पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा-अर्चना की थी। शारदा देवी का मंदिर सिर्फ आस्था और धर्म के नजरिये से खास नहीं है। इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है।

माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। इसमें बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कलियुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे।

दुनिया के जाने-माने इतिहासकार ए कनिंग्घम ने इस मंदिर पर विस्तार से शोध किया है। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जूदेव ने पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया।

कैसे पहुंचे मंदिर- राजधानी दिल्ली से मैहर तक की सड़क से दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। ट्रेन से पहुंचने के लिए महाकौशल व रीवा एक्सप्रेस उपयुक्त हैं। दिल्ली से चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस सीधे मैहर ही पहुंचती है।

स्टेशन से उतरने के बाद किसी धर्मशाला या होटल में थोड़ा विश्राम करने के बाद चढ़ाई आरंभ की जा सकती है। रीवा एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले भक्तजनों को मजगांवां पर उतरना चाहिए। वहां से मैहर लगभग 15 किलोमीटर दूर है।

त्रिकूट पर्वत पर मैहर देवी का मंदिर भू-तल से छह सौ फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक जाने वाले मार्ग में तीन सौ फीट तक की यात्रा गाड़ी से भी की जा सकती है। मैहर देवी मां शारदा तक पहुंचने की यात्रा को चार खंडों में विभक्त किया जा सकता है।

प्रथम खंड की यात्रा में चार सौ अस्सी सीढ़ियों को पार करना होता है। मंदिर के सबसे निकट त्रिकूट पर्वत से सटा मंगल निकेतन बिड़ला धर्मशाला है। इसके पास से ही येलजी नदी बहती है। द्वितीय खंड 228 सीढ़ियों का है।

इस यात्रा खंड में पानी व अन्य पेय पदार्थों का प्रबंध है। यहां पर आदिश्वरी माई का प्राचीन मंदिर है। यात्रा के तृतीय खंड में एक सौ सैंतालीस सीढ़ियां हैं। चौथे और अंतिम खंड में 196 सीढ़ियां पार करनी होती हैं। तब मां शारदा का मंदिर आता है।

गैस, एसिडिटी और डकार आने का संभावित कारण

1. वात दोष / वायु विकार डकार मुख्यतः वायु विकार का संकेत है।
2. खाली पेट में गैस निर्माण. देर रात तक खाली पेट रहना।
3. कुपाचन (Indigestion) दिन भर का खाना अच्छे से पच न पाना।
4. अनियमित भोजन समय.
5. रात का खाना देर से या बहुत भारी खाना।
6. . नर्वस सिस्टम / एंग्जायटी....
7. कुछ मामलों में चिंता से भी डकार आती है।
8. Silent Reflux .एसिडिटी जैसा लक्षण न होते हुए भी डकारें आ सकती हैं।

स्थायी उपाय (प्राकृतिक और आयुर्वेदिक)

1. भोजन सुधार (Diet Correction)....

समय कार्य रात 7:00 PM तक हल्का, सुपाच्य भोजन करें (उदाहरणः मूंग की खिचड़ी, दलिया, सूप)

भोजन के बाद 100 कदम टहलना

दिनभर में अत्यधिक तला-भुना, चाय, कॉफी, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स से बचें

2. आयुर्वेदिक घरेलू उपाय

हिंगवासव (Hingwasava) – 2 चम्मच पानी के साथ, रात को भोजन के बाद

अविपत्तिकर चूर्ण – 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले

त्रिफला चूर्ण – 1 चम्मच गर्म पानी में, रात को (यदि कब्ज है)

जीरा + अजवाइन + सौंठ का पाउडर – समान मात्रा में मिलाकर, आधा चम्मच भोजन के बाद लें

3. लाइफस्टाइल सुधार रात को लेटने से पहले 2 घंटे का गैप रखें भोजन और नींद के बीच,

मोबाइल/स्क्रीन का उपयोग कम करें रात में

बाएं करवट लेटें – इससे डाइजेशन में मदद मिलती है

दिन में कम से कम 20 मिनट वॉक या योगासन

4. योग और प्राणायाम

वज्रासन (भोजन के बाद 5-10 मिनट)

अनुलोम-विलोम (रोज़ 10 मिनट)

पवनमुक्तासन (सुबह खाली पेट,) करना चाहिए

H. Pylori टेस्ट कभी-कभी करना चाहिए – यह बैक्टीरिया पेट में गैस और डकार की समस्या दे सकता है

आयुर्वेद अपनाएं स्वस्थ जीवन पाएं.

विचार प्रवाह

1. केवल खुद सज्जन बने रहना पर्याप्त नहीं है – अगर समाज में बुराई फैल रही है तो सज्जनों का यह कर्तव्य है कि वे उसका प्रतिरोध करें।

2. अपराध रोकने का कर्तव्य – यदि हम अपराध या अनाचार होते देखें और चुप रहें, तो यह भी एक प्रकार का अपराध माना जाएगा।

3. सामूहिक जिम्मेदारी समाज एक नाव के समान है। यदि एक व्यक्ति छेद करेगा और बाकी चुप रहेंगे, तो नाव सबको लेकर डूबेगी।

4. बुराई का असर सब पर पड़ता है – चाहे हम सीधे उस गंदगी में शामिल न हों, लेकिन उसका वातावरण हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर देता है।

5. विरोध की शक्ति – जैसे स्वतंत्रता संग्राम में आवाज उठाने से भारत आज़ाद हुआ, वैसे ही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संगठित और प्रबल विरोध से समाज को सुधारा जा सकता है।

यानी, अगर हम पाप के खिलाफ खड़े नहीं

अदरक के बारे में ये जानकारी पता है आपको ?

सर्दी खांसी, जुकाम, पेट दर्द, मोशन सिकनेस, जी मिचलाना और अपचन होने पर अदरक का इस्तेमाल तो खूब करते हैं आप लेकिन पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं, ये दुनिया के तमाम दर्द निवारकों (पेन किलर्स) में से एक बेहतरीन दर्द निवारक ऑप्शन है। वजह है इसमें पाए जाने वाले कमाल के फाइटोकेमिकल्स। जिन्जेरॉल्स और शोगोल्स ऐसे नेचरल कंपाउंड्स हैं जिनके पाए जाने की वजह अदरक खासम ख़ास है।

थोड़ी काम की बात करते हैं

अदरक कमाल का दर्द निवारक भी है। दर्द निवारक, वो भी इतना तगड़ा कि आइबूप्रोफेन, ट्रिप्टान और NSAID (नॉन स्टेरॉइडल एंटीइंफ्लेमेटरी ड्रग) के टक्कर का। एक क्लिनिकल स्टडी बताती है कि माइग्रेन में आराम दिलाने वाली मेडीसिन ट्रिप्टान और अदरक का असर बिल्कुल एक जैसा है। इस क्लीनिकल स्टडी में माइग्रेन के रोगियों के दो ग्रुप बनाए गए, एक को ट्रिप्टान और दूसरों को सोंठ (सुखाया हुआ अदरक) का पाउडर दिया गया, दोनों दवाओं को लेने के २ घंटे के भीतर दर्द में सभी लोगों को आराम मिल गया। एक है नेचरल ऑप्शन और दूसरा सिंथेटिक।

इसी तरह की एक और स्टडी का जिक्र जान लीजिये पीरियड्स में दर्द की शिकायत वाली 150 महिलाओं के दो ग्रुप्स में से एक को अदरक और दूसरे को आइबूप्रोफेन या NSAID दिए गए और पाया गया कि दोनों ही ग्रुप की महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में बराबरी से दर्द में राहत मिली।

अदरक तो बेशक कमाल का पेन किलर है, आर्थराइटिस से ग्रस्त लोगों को भी ये गज़ब आराम दिलाता है। अब सबसे जोरदार बात अदरक और भी कई जबर्दस्त काम करता है.

ये जो दुनियाभर की हाई डोज़ पेनकिलर मेडिसिन्स आप निगलते हैं ना, उनके जो-जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, उन्हें भी चंगा कर देता है।

क्लीनिकल स्टडीज़ बताती हैं कि हेवी डोज़ ड्रग्स की वजह से पेट की भीतरी लाइनिंग के डैमेज को कम करने या उसे ठीक करने में अदरक के फाइटोकेमिकल्स कमाल का काम करते हैं।

दर्द सताए तो 15-२0 ग्राम कुचलें अदरक, रस निकालें और गटक जाएं, दर्द वाले हिस्से पर बचे हिस्से का लेप करके रखें, आधा घंटा।

सोंठ का पाउडर भी रसोई में रखें, पाउडर की 5-7 ग्राम (एक चम्मच) मात्रा एक कप गुनगुने में मिक्स करके पी जाएं,

ध्यान रहे,

1. तब करना है जब दर्द सता रहा हो। और
२. आँख में ना जाए

"हवन के फायदे"

फ़्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की। जिसमें उन्हें पता चला की हवन मुख्यतः आम की लकड़ी पर किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फ़ॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है तथा वातावरण को शुद्द करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने का तरीका पता चला।

गुड़ को जलाने पर भी ये गैस उत्पन्न होती है।

टौटीक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गयी अपनी रिसर्च में ये पाया की यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाये अथवा हवन के धुएं से शरीर का सम्पर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फ़ैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है।

हवन की महत्ता देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसन्धान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर एक रिसर्च की। क्या वाकई हवन से वातावरण शुद्द होता है और जीवाणु नाश होता है ?अथवा नही ? उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलाने पर पाया कि ये विषाणु नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी काम किया और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी १ किलो जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हुए। पर जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डाल कर जलायी गयी तो एक घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर ९४% कम हो गया।

यही नहीं उन्होंने आगे भी कक्ष की हवा में मौजुद जीवाणुओ का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाज़े खोले जाने और सारा धुआं निकल जाने के २४ घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से ९६ प्रतिशत कम था। बार-बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस एक बार के धुएं का असर एक माह तक रहा और उस कक्ष की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था।

यह रिपोर्ट एथ्नोफार्माकोलोजी के शोध पत्र (resarch journal of Ethnopharmacology 2007) में भी दिसंबर २००७ में छप चुकी है। रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों एवं फसलों को नुकसान पहुचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है। जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है।

सनातन, हिंदू धर्म और हिंदुत्व की सदैव ही जय

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एनडीएमए द्वारा प्रशिक्षित आपदा मित्र/सखी को सरकारी आपदा कर्मचारी का दर्जा देकर नियमित मानदेय प्रदान करने की उठी मांग

नवदीप सिंह

बिहार राज्य के आपदा मित्र/सखी द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार सरकार को लिखित में ज्ञापन सौंप कर उठाई मांग।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एनडीएमए द्वारा प्रशिक्षित आपदा मित्र/सखी को सरकारी आपदा कर्मचारी का दर्जा देकर नियमित मानदेय प्रदान करने के संबंध में मुख्यमंत्री से निवेदन कर बताया बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य में आपदा से निपटने हेतु 9600 आपदा मित्र/सखियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन प्रशिक्षित आपदा मित्रों द्वारा समय-समय पर विभिन्न अवसरों पर दायित्व निभाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में छठ महापर्व के अवसर पर राज्यभर में आपदा मित्र/सखियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। किंतु, वर्ष 2024 में आपदा मित्रों/सखियों को ड्यूटी पर नहीं लगाया गया, जिसके दौरान पूरे बिहार में 72 लोगों की मृत्यु हुई। इस कारण राज्य सरकार को आपदा पीड़ित परिवारों को ₹2 करोड़ 88 लाख का मुआवजा प्रदान करना पड़ा। अगर हम सभी आपदा मित्रों को ड्यूटी लगाई जाती तो सरकार की इतना पैसा खर्च नहीं होता महाशय हम सभी युवा प्रशिक्षण लेकर बेरोजगार बैठे हैं कभी कभी हम लोगों से काम लिया जाता है हम लोगों को स्थायी नियुक्ति कर दिया जाए जिससे हम लोगों का जीविकोपर्जन सही ढंग से हो सके

हम सभी आपदा मित्रों/सखियों को सरकारी आपदा कर्मचारी घोषित किया जाए और केंद्र की एक ही योजना के तहत प्रशिक्षित आपदा मित्रों/सखियों का समायोजन कर कार्य एवं वेतन निर्धारित किया जाए। इसके लिए हम सभी आपदा मित्र/सखी आपका अभारी रहूंगा।

समस्त बिहार राज्य
आपदा मित्र/सखी

अनुबंधित कर्मचारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और समान वेतन की मांग

हंसराज

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम के कांटेक्ट एवं नियमित कर्मचारी इस महान संस्था की रीड है, यह वे लोग हैं जो दिन-रात तपते सूरज, बरसते बादल और ठिठुरती सर्दी में भी बिना रुके बिना थके निगम हित को अपनी सेवा का परम ध्येय मानकर कार्यरत रहते हैं। उनका जीवन निगम की धड़कन है उनकी निष्ठा निगम की पहचान है।

परंतु हृदय को अत्यंत पीड़ा तब होती है जब परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में भेदभाव किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट चालक और परिचालक के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है जबरदस्ती ओके ड्यूटी करने का प्रेशर बनाया जाता है, कर्मचारी को मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है, और यही भेदभाव परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी किया जाता है जो कर्मचारी स्वयं को निगम का परिवार मानकर उसकी सेवा में दिनरात्रि एक कर देते हैं क्या वह केवल अपमान और समान कार्य के कम वेतन के ही पात्र हैं?

श्रीमान जी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की आज के समय में मानसिक और आर्थिक स्थिति दोनों खराब होती जा रही है जिस कारण वे अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तथा न हीं खुद के लिए उच्च गुणवत्ता वाला भोजन तक प्राप्त कर पा रहे हैं, इतनी कम सैलरी मात्र 862 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त करने पर दिल्ली जैसे शहर में अपने घर और परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं जिससे कई कर्मचारियों ने आत्महत्या तक कर ली है जब कर्मचारियों का वेतन ही निम्न स्तरीय होगा तो कर्मचारी की मानसिक सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि स्वास्थ्य ही दुर्बल होगा तो निगम अपने स्वप्निल लक्षण की ऊंचाई तक कैसे पहुंच पाएगा?

आपके नेतृत्व और दूर दृष्टि से आज निगम प्रगति पथ पर अग्रसर है। किंतु अनुबंधित कर्मचारियों की यह स्थिति होना एक काला धब्बा है। तथा इतनी खराब हो स्थिति होने के बाद यात्रियों की पहली छवि वही होता है, इतनी स्थिति खराब होने के बाद में केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि आमजन का विश्वास भी डगमगा जाता है।

अतः विनम्र निवेदन है कि इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए आप तत्वरिक एवं ठोस कार्यवाही करें, ताकि -

1. निगम के कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिल सके
2. यात्रियों को सकारात्मक अनुभव प्राप्त हो सकेगा
3. निगम के कर्मचारियों को रोजगार की सुनिश्चितता मिल सके
4. निगम की गरिमा और प्रतिष्ठा अनुच्छण बनी रहेगी

हम सभी कांटेक्ट के कर्मचारी आपसे आशा करते हैं आपके करुणा में हृदय और सशक्त नेतृत्व से यह समस्या शीघ्र समाप्त होगी और निगम परिवार का हर सदस्य स्वयं को सुरक्षित सम्मानजनक और गौरवान्वित अनुभव करेगा।

रक्षा द सेवियर एवं टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) की ओर से

गरबा महोत्सव में विशेष अपील

हमारी रक्षा द सेवियर एवं टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) की ओर से रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है—
इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें:

- पुराने कपड़े
- पुराने कंबल
- पुराने जूते-चप्पल
- बच्चों के लिए बैग
- किताबें

आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है

स्थान : रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

इंदु राजपूत – 9210210071,
अभिषेक राजपूत 83928 02013,
पिंकी कुंडू 7053533169

देश का अल्पसंख्यक व्यापारी भी कर रहा है मोदी जी का धन्यवाद : अनीश अब्बासी

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। मोदी सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी में दी गई राहत को लेकर देशभर में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस फैसले ने आम व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच नई उम्मीदें जगाई हैं। कारोबारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से व्यापार को गति मिलेगी, महँगाई पर नियंत्रण रहेगा और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मोर्चा अध्यक्ष अनीश अब्बासी के नेतृत्व में आज जामा मस्जिद क्षेत्र के विभिन्न बाज़ारों में पहुँचे। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों, ग्राहकों और खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से उनकी राय जानी तो स्थानीय लोगों ने जीएसटी में राहत देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम आम जनता के हित में है और निश्चित रूप से इसका फायदा हर व्यक्ति को मिलेगा।

व्यापारियों और ग्राहकों का कहना है कि इससे छोटे दुकानदारों, रोज़मर्रा के सामान खरीदने वालों और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि मोदी सरकार ₹सबका साथ, सबका विकास₹ के मंत्र पर चलकर हर वर्ग की फिक्र करती है बस ये समझ का फेर है।

इस दौरान इस अभियान में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी कारी मोहम्मद हारून, दिल्ली प्रदेश सह कार्यालय प्रभारी अमित गुप्ता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दीप्ति इंदौरा सहित मुस्लिम समाज के अनेकों गणमान्य लोग वा मोर्चे के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इस मौके पर अनीश अब्बासी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीब, व्यापारी और आम नागरिक की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं। जीएसटी में दी गई राहत इसका ताज़ा उदाहरण है।

उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल मुस्लिम समाज बल्कि पूरे देश की जनता के लिए राहतकारी और ऐतिहासिक साबित होगा।

यह रचना दिल को छू गई।

तीन पहर तो बीत गये,
बस एक पहर ही बाकी है।
जीवन हाथों से फिसल गया,
बस खाली मुट्ठी बाकी है।

सब कुछ पाया इस जीवन में,
फिर भी इच्छाएं बाकी हैं
दुनिया से हमने क्या पाया,
यह लेखा - जोखा बहुत हुआ,
इस जग ने हमसे क्या पाया,
बस ये गणनाएं बाकी हैं।

इस भाग-दौड़ की दुनिया में
हमको इक पल का होश नहीं,
वैसे तो जीवन सुखमय है,
पर फिर भी क्यों संतोष नहीं !

क्या यूं ही जीवन बीतेगा,
क्या यूं ही सांसें बंद होंगी ?
औरों की पीड़ा देख समझ
कब अपनी आंखें नम होंगी ?
मन के अंतर में कहीं छिपे
इस प्रश्न का उत्तर बाकी है।

मेरी खुशियां, मेरे सपने
मेरे बच्चे, मेरे अपने
यह करते - करते शाम हुई

तीन पहर तो बीत गये,
बस एक पहर ही बाकी है।
जीवन हाथों से फिसल गया,
बस खाली मुट्ठी बाकी है।

*जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है! अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, यदि यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है.
आइए, मंथन करे

छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए, एनडीएमसी ने राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के साथ एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने आज राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र (एनएससी), प्रगति मैदान, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह सहयोग एनडीएमसी शिक्षा विभाग के तहत अपनी तरह की पहली पहल है, जो माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इस साझेदारी के माध्यम से, एनडीएमसी और नवयुग स्कूलों के 5,000 स्कूली छात्र एनएससी में निर्देशित पर्यटन और इंटरैक्टिव विज्ञान शो का अनुभव करेंगे। साथ ही, 1,200 छात्र रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में व्यावहारिक नवाचार सत्रों में भाग लेंगे।

एनडीएमसी स्कूलों के विज्ञान शिक्षकों को कक्षा शिक्षण को समृद्ध बनाने के लिए कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्री डिजाइन और विकसित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

इस अवसर पर बोलते हुए, एनडीएमसी की निदेशक (शिक्षा) कृतिका चौधरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह सहयोग न केवल छात्रों की वैज्ञानिक सोच को मज़बूत करेगा, बल्कि उन्हें नवाचार और अन्वेषण के लिए भविष्य के लिए तैयार कौशल से भी लैस करेगा।

यह ऐतिहासिक पहल जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनडीएमसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में सार्थक योगदान मिलेगा।

"आप" सरकार में स्थायी समिति का मुद्दा उठाने वाली भाजपा आज खुद आपसी खींचतान में दिल्ली का काम रोक रही है- अंकुश नारंग

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। भाजपा तमाम हथकंडे अपनाकर दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज तो हो गई, लेकिन अब उसके मेयर और स्थायी समिति की अध्यक्ष के बीच झगड़े शुरू होने का खमियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आगामी 24 सितंबर को स्थायी समिति की बैठक होने वाली थी और उसके सर्कुलर, एजेंडा भी छप गए लेकिन स्थायी समिति की मीटिंग ही रद्द हो गयी। मेयर राज इकबाल सिंह और स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा के बीच सामने आ रहे मतभेदों को लेकर भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए एमसीडी में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने ये बातें कहीं।

अंकुश नारंग ने कहा कि अभी तक हुई स्थायी समिति की बैठकों में दिल्ली की जनता के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया है। लैंडफिल साइट और राजस्व से जुड़े अहम फैसले महापौर राजा इक़बाल सिंह ने अधिकारियों से मिलीभगत कर समिति को दरकिनार करते हुए सीधे खुद ले लिए। जबकि नियम है कि सभी रेवेन्यू मैटर्स स्थायी समिति में ही आने चाहिए। महापौर लगातार समिति को बाईपास कर खुद फैसले करके प्रस्तावों को सीधे सदन में पेश कर रहे हैं। एमसीडी की स्थायी समिति को महापौर ने सभी रेवेन्यू मैटर्स से भी दरकिनार किया हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार में समिति न बनने पर सवाल उठाने वाली भाजपा अब अपनी ही आपसी खींचतान में दिल्ली की जनता का काम रोक रही है।

उन्होंने कहा कि जब से स्टैंडिंग कमेटी बनी है, तब से अब तक सिर्फ तीन बैठकें हुई हैं। तीन बैठकों में कोई अहम फैसले नहीं लिए गए। आज तक पुराने लंबित मामले ही चल रहे हैं, कोई नए मामले नहीं आए। एस्ट्रॉइड शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुद्दे पर भाजपा ने एक निजी आवास समिति वाले बिल्डर का फायदा किया। इस मुद्दे को मेयर सीधे सदन में ले आए, जबकि उसके अंदर संपत्ति हटाने वाला मुद्दा था, जिसमें एमसीडी का खत्ता और डेम्स का कार्यालय हटाना था। लेकिन मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी का इंतजार नहीं किया, सीधा सदन के अंदर ले आए।

अंकुश नारंग ने बताया कि भाजपा ने यूजर चार्ज का मुद्दा स्टैंडिंग कमेटी में लाने की बात कही। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के दबाव से यूजर चार्ज का मुद्दा सीधा सदन में लाया गया और इन्होंने उसे सदन से पास करा लिया।

उन्होंने बताया कि भाजपा ने भूमिगत मार्ग के मुद्दे को जानबूझकर पहले टाला, फिर बाद में पास किया। आरोप लग रहे है कि भाजपा के लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। समिति की बैठक में कोई नया मुद्दा नहीं आ रहा। रियायत का मुद्दा भी सीधे सदन में आया, जबकि उसे स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहिए था, क्योंकि यह राजस्व का मामला था। लैंडफिल के मुद्दे को भी सीधे स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहिए था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आया, वह भी सीधे सदन में जा रहा है।

अंकुश नारंग ने कहा कि महापौर ने स्टैंडिंग कमेटी की कोई भूमिका नहीं छोड़ी है। भाजपा पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उनके महापौर और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। इससे दिल्ली की जनता का भारी नुकसान हो रहा है। भाजपा ने दिल्ली की जनता को किनारे कर दिया है, जबकि जनता ने अपेक्षाओं के साथ विधानसभा में भाजपा को 48 सीटें देकर दिल्ली सरकार सौंपी। एमसीडी और केंद्र में भी भाजपा ही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की चार इंजन वाली सरकार से उम्मीद थी कि एमसीडी शानदार काम करेगी, लेकिन भाजपा ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। जगह-जगह कूड़ा ही मिलता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भाजपा के पास कोई योजना नहीं है, एमसीडी पर वह बिल्कुल ध्यान नहीं देती। आरोप है कि भाजपा सिर्फ अपनी जेब भरने पर ध्यान देती है।

एकात्मता के जीवंत पर्याय: पंडित दीनदयाल उपाध्याय

-संदीप सृजन

भारतीय चिंतन परंपरा में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो न केवल एक विचारधारा के प्रणेता होते हैं, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही एक महान दार्शनिक, समाजसेवी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें 'एकात्मता' का जीवंत पर्याय कहा जा सकता है। एक साधारण परिवार में जन्मे प. दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन को राष्ट्रसेवा और मानवीय मूल्यों के प्रचार में समर्पित कर दिया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक बने, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और बाद में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान 'एकात्म मानववाद' के रूप में सामने आया, जो भारतीय विकास के लिए एक स्वदेशी दर्शन है। यह दर्शन न तो पूंजीवाद की भौतिकवादिता को अपनाता है और न ही साम्यवाद की वर्ग-संघर्ष की हिंसा को। बल्कि, यह मानव को सृष्टि के केंद्र में स्थापित करते हुए एक समग्र, एकात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एकात्मता का पर्याय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव जीवन के सभी आयामों—शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक—को एक सूत्र में बांध दिया। आज जब विश्व आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट और नैतिक पतन से जूझ रहा है, तो उनका दर्शन प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। उनके विचारों में एकता की भावना इतनी गहरी थी कि वे व्यक्ति को समाज से अलग नहीं मानते थे, बल्कि दोनों को एक-दूसरे का पूरक बताते थे। उदाहरण के लिए, वे अक्सर कहते थे कि ₹मानव का विकास तभी संभव है जब वह अपने आस-पास की सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करे।₹ यह विचार भारतीय वेदांत दर्शन से प्रेरित था, जहां 'अहं ब्रह्मास्मि' की अवधारणा मानव को ब्रह्मांड का हिस्सा बनाती है। दीनदयाल जी ने इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में ढाला, जिससे उनका दर्शन न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बना।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन संघर्षों और त्याग की मिसाल है। मात्र सात वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और नौ वर्ष की उम्र में मां का साया भी छिन गया। अनाथ हो जाने के बावजूद, उन्होंने अपनी शिक्षा में कभी रुकावट नहीं आने दी। उनके मामा ने उन्हें पाला और शिक्षा दी। उन्होंने कानपुर से मैट्रिक पास किया, फिर पिलानी से इंटरमीडिएट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद, उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के दौरान वे विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए। 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और मात्र 23 वर्ष की आयु में प्रचारक बन गए।

प्रचारक के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में संघ कार्य का विस्तार किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को संगठित किया, शिक्षा और स्वास्थ्य शिविर लगाए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे सक्रिय रहे और जेल भी गए।

1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे जनसंघ के महासचिव बने और संगठन को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए। 1967 में वे जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन उनका राजनीतिक सफर छोटा रहा। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई, जिसकी जांच आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह राजनीतिक षड्यंत्र था, जबकि आधिकारिक रिपोर्ट दुर्घटना बताती है। मात्र 51 वर्ष की आयु में वे चले गए, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। उनकी मौत के बाद जनसंघ ने उनकी स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किए, और आज भी मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सादगी, अनुशासन और सेवा का प्रतीक था। वे कभी सत्ता के लोभ में नहीं पड़े। जनसंघ को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है: ₹राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि सेवा है।₹ उनका जीवन एकात्मता का जीता-जागता उदाहरण था, जहां व्यक्तिगत सुख को त्यागकर सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। वे कभी महंगे कपड़े या सुख-सुविधाएं नहीं अपनाते थे। एक बार जब वे जनसंघ के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने कहा कि ₹मैं पद का दुरुपयोग नहीं करूंगा, बल्कि इसे सेवा का माध्यम बनाऊंगा।₹ उनके सहयोगी बताते हैं कि वे हमेशा साइकिल से यात्रा करते थे और सादा भोजन करते थे। यह सादगी उनके दर्शन का हिस्सा थी, जो भौतिकवाद से दूर रहने की सलाह देती है।

एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यह दर्शन 1965 में बॉम्बे (अब मुंबई) में आयोजित भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में विस्तार से प्रस्तुत किया गया। 'एकात्म' शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'एक साथ जुड़ा हुआ' या 'समग्र'। मानववाद का तात्पर्य मानव को केंद्र में रखना है। इस दर्शन के अनुसार, मानव सृष्टि का अभिन्न अंग है। वह न तो केवल भौतिक शरीर है और न ही आत्मा का अलगाव। बल्कि, वह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एकात्मिक संयोग है। दीनदयाल जी कहते थे, ₹मानव को उसके सम्पूर्ण रूप में देखना ही एकात्म मानववाद है।₹ उन्होंने इस दर्शन को चार व्याख्यानों में प्रस्तुत किया, जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए।

शिक्षा महाकुंभ 2025 भारत की शैक्षिक पुनर्जागरण यात्रा में योगदान देने के लिए आमंत्रण- डा.अमित कांसल

नाइपर मोहाली करेगा शिक्षा महाकुंभ अभियान 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी, 31 अक्टूबर से होगा आयोजन

संगरूर,24 सितंबर (जगसीर लोगोंवाल)-

तीन दिवसीय शिक्षा महाकुंभ अभियान 2025 का 5वां संस्करण 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2025 तक नाइपर मोहाली में आयोजित किया जाएगा। "क्लासरूम टू सोसाइटीः बिल्डिंग अ हेल्थियर वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन" थीम के साथ यह कॉन्क्लेव अकादमिक जगत, शोध, उद्योग और नीति के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर भारत में शिक्षा के भविष्य की नई कल्पना करेगा।

मीडिया से एक विशेष भेंट वार्ता के दौरान शिक्षा महाकुंभ की केंद्रीय मीडिया टोली के सदस्य डॉ अमित कंसल ने जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा महाकुंभ अभियान 2025 शिक्षा की सोच को समाज की जरूरतों के साथ जोड़ने वाला एक वैश्विक सशक्त मंच सिद्ध होगा।

डॉ कांसल ने आगे कहा कि शिक्षा महाकुंभ एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा है, जो शिक्षा को नवाचार, मूल्यों और सांस्कृतिक भावनाओं से जोड़ता है। शिक्षा महाकुंभ अभियान अपने हर हितधारक—छात्र, शिक्षक, संस्थान, उद्योग और नीति-निर्माता—के लिए भारत की शैक्षिक पुनर्जागरण यात्रा में योगदान देने का आमंत्रण है, जो भारत@2047 की परिकल्पना के अनुरूप है।

डॉ कांसल ने कहा कि होलिस्टिक एजुकेशन विभाग (डीएचई) द्वारा नाइपर मोहाली के सहयोग से और राज्य एवं केंद्र की प्रमुख संस्थाओं के समर्थन से आयोजित इस 5वें संस्करण में कई आयोजन होंगे। इनमें 12 राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव में वाईस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, टीचर्स, शोधकर्ताओं, नवाचारकों और नीति-निर्माताओं की हिस्सेदारी रहेगी।साइंस, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, नेशनल टिनकेरिंग चैलेंज, शिक्षा प्रौद्योगिकी और सत्तता पर पेपर प्रस्तुतियाँ; स्टूडेंट्स सेंट्रिक प्रोग्राम जैसे नेशनल टिंकरिंग चैलेंज, विद्यार्थी संस्कार सम्मेलन, भारत यात्रा क्विज़, इंग्लिश ओलंपियाड और स्टार्टअप शोकेस, एग्जीबिशन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और अवार्ड्स इस शिक्षा महाकुंभ के मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे।

डॉ कंसल ने कहा कि सालों से डी एच ई ने कई पहलें प्रेरित की हैं जैसे—ट्रेडुल, सर्वत्र, स्वदेशी बाज़ार, जॉब्स 360 डिग्री, टुडू, होलिस्टिक हार्बर, विद्या भारती ओलंपियाड और भारत सुपर 100—जिन्होंने शिक्षा को समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ा है।

एआईओसीडी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र

छोटे केमिस्टों को तीन माह तक पुरानी एमआरपी पर दवाएँ बेचने की दी जाए अनुमति

जीएसटी कमी से छोटे खुदरा विक्रेताओं के घाटे को राहत प्रदान करने की मांग

संगरूर,(जगसीर लोगोंवाल) -ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी), जो देशभर के 12.5 लाख से अधिक केमिस्टों और वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने दिनांक 22 सितम्बर 2025 से लागू जीएसटी 2.0 तथा कर दरों में कमी का हृदय से स्वागत किया है। एआईओसीडी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिखकर इस निर्णय और दूरदर्शी सुधार की सराहना की है । एआईओसीडी से जुड़े पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य नरेश जिंदल ने बताया कि पत्र में देशभर के छोटे केमिस्ट का मुद्दा उठाया गया है । देशभर में नई जीएसटी दरों के अनुसार मूल्य संशोधन किया है, लेकिन छोटे खुदरा दवा विक्रेताओं की समस्याओं की कोई सुध नहीं ली जा रही है।छोटे केमिस्ट (उर्द एवं कंपोज़िट), विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, पहले से ही शासन द्वारा निर्धारित बहुत कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं।

18% से 5%, 12% से 0% और 12% से 5% की दर में कमी के कारण अब उन्हें अपने पुराने स्टॉक (जो उच्च जीएसटी दरों पर खरीदा गया था) कम कीमतों पर बेचना पड़ रहा है। जबकि दवाओं पर मार्जिन एनपीपीए द्वारा तय किया जाता है। ऐसे छोटे खुदरा विक्रेता इस कर अंतर से घाटा उठा रहें हैं और चुकाया हुआ कर वसूल नहीं कर पा रहें हैं, वे या तो कम्पोजिशन डीलर हैं या छोटा व्यापर होने की वजह से जीएसटी में पंजीकृत भी नहीं हैं, अतः वे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा भी नहीं कर सकते ।अनेक स्थानों पर इन छोटे व्यापारियों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने 21 सितम्बर तक छोटे उर्द और कंपोज़िट खुदरा विक्रेताओं को बिके माल पर पूरा जीएसटी पहले ही वसूल कर लिया है, उनकी वर्तमान स्थिति को अनदेखा किया जा रहा है ।इसके विपरीत, इन व्यापारियों को घाटे में बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है. जो अन्यायपूर्ण और अस्थिर स्थिति है ।आपसे विनम्र निवेदन है कि छोटे खुदरा विक्रेताओं और केमिस्टों की रक्षा करें। सरकार कम-से-कम आगामी तीन माह तक पुरानी एमआरपी पर दवाओं के पाइप लाइन स्टॉक की बिक्री की अनुमति प्रदान करे, ताकि उच्च दरों पर खरीदे गए वर्तमान स्टॉक को बिना और अधिक घाटा उठाए विक्रय किया जा सके ।यदि यह संभव न हो तो छोटे व्यापारियों और केमिस्टों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए जिससे उनके वित्तीय नुकसान की भरपाई हो सके ।जब तक यह तीन माह की संक्रमण अवधि पूरी न हो जाए, तब तक छोटे खुदरा विक्रेताओं के साथ किसी भी प्रकार की परेशानी, उत्पीड़न या दंडात्मक कार्यवाही न की जाए, क्योंकि वे पहले से ही गहरे संकट का सामना कर रहे हैं। यदि तत्काल राहत न दी गई तो अनेक छोटे केमिस्ट अपनी दुकानें बंद करने के लिए विवश हो जाएंगे, जिससे विशेषकर दूरदराज़ क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

आजम खान पर कुल 111 केस, अकेले 2019 में दर्ज हुए 70; ट्रैफिक रोकने से लेकर जमीन कब्जा तक के आरोप

रिपोर्ट अंकित गुप्ता दिल्ली

आजम खान पर कुल 111 केस, अकेले 2019 में दर्ज हुए 70; ट्रैफिक रोकने से लेकर जमीन कब्जा तक के आरोप

आजम खान के खिलाफ कुल 111 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 70 मामले 2019 में दर्ज किए गए थे। उन पर यातायात बाधित करने और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है।

आजम खान पर कुल 111 केस, अकेले 2019 में दर्ज हुए 70। फोटो सोर्स- पत्रिका

मोहम्मद आजम खान मंगलवार दोपहर सीतापुर जेल से रिहा हो गए। लगभग 2 साल जेल में रहने के बाद यह उनकी दूसरी रिहाई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक माने जाने वाले खान ने कई सालों तक पार्टी में अहम भूमिका निभाई है।

आजम खान की पत्नी और बेटे पर भी लगे आरोप

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन पर भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज होने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें शुरू हुईं। जिसके बाद कई और मामले दर्ज हुए। तब से उनके खिलाफ लगातार मामले बढ़ते गए। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर भी कई आरोप लगे।

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Case Update

'सिर्फ पैसों की चाह में मम्मा भानवी सिंह ने....', राजा भैया के बेटे ने उठा दिया अबतक 'छिपे राज' से पर्दा!

आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने दी बधाई।

आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान, 'सपा सरकार बनने पर फर्जी केस वापस लेंगे'

रामपुर सदर से 10 बार के विधायक आजम खान जेल से रिहा

मंगलवार को खान को सभी 79 आपराधिक मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। रामपुर सदर से 10 बार के विधायक खान को रामपुर की अलग-अलग अदालतों के साथ-साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी उच्च अदालतों से भी अलग-अलग समय पर जमानत मिली।

सीतापुर जेल के अधीक्षक ने क्या कहा?

सीतापुर जेल के अधीक्षक सुरेश सिंह का कहना है, ₹सभी मामलों में रिहाई का आदेश मिलने के बाद ही आजम खान को रिहा किया गया।₹ जिस आखिरी मामले में उन्हें जमानत मिली, वह 2020 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी और उससे जुड़े अपराधों के आरोप में दर्ज किया गया था।

आजम खान के खिलाफ कुल 111 मामले

उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, आजम खान के खिलाफ कुल 111 मामले हैं, जिनमें से 5 मामले रामपुर के बाहर दर्ज हैं। लखनऊ और फिरोजाबाद में एक-एक और मुरादाबाद में 3। इनमें से 81 से ज्यादा मामले 2017 में राज्य में BJP की सरकार बनने के बाद दर्ज किए गए। इनमें से लगभग 70 मामले 2019 में और 6 मामले 2020 में दर्ज किए गए। इन मामलों में जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, तोड़फोड़, जबरन घुसपैठ, भड़काऊ भाषण और आपराधिक धमकी जैसे कई आरोप शामिल हैं।

आजम खान पर जमीन हड़पने का आरोप

कई मामले खास तौर पर इस आरोप से जुड़े हैं कि खान और उनके साथियों ने रामपुर के डोंगरपुर इलाके में जमीन हड़पने की कोशिश की। अधिकारियों का दावा है कि इस जमीन पर बने घरों को अवैध कब्जे के आधार पर तोड़ा गया और बाद में इस संपत्ति का इस्तेमाल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए किया गया, जिसकी स्थापना खान ने की थी। वही इसके चांसलर भी हैं।

2022 में, रामपुर पुलिस ने खान और उसके साथियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। आरोप था कि विश्वविद्यालय परिसर में सफाई मशीनें दबी हुई मिलीं। बताया जाता है कि रामपुर नगर पालिका द्वारा खरीदी गई ये मशीनें परिसर में अलग-अलग हिस्सों में बिखेरकर दफना दी गई थीं। पुलिस का दावा है कि उन्हें यह जानकारी एक दूसरे मामले में आरोपी से पूछताछ के दौरान मिली और बाद में परिसर से मशीनें बरामद की गईं।

बाकी है अभी लड़ाई...

यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, आजम खान 6 मामलों में दोषी पाया गया है - पांच रामपुर में और एक मुरादाबाद में। इन सभी मामलों में उसे जमानत मिल गई है। 2008 के एक मामले को छोड़कर, बाकी सभी मामले 2019 में दर्ज किए गए थे। इन मामलों में आरोप घर में घुसने, तोड़फोड़, नफरत फैलाने वाले भाषण और यातायात बाधित करने जैसे हैं। हालांकि आजम खान जमानत पर रिहा हुए हैं लेकिन उनके खिलाफ दर्ज हुए प्रकरणों की जांच जारी है।

"टैरिफ स्टेटमेंट पर आत्मनिर्भरता से ही ट्रम्प को बैकफुट पर लाएंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी: प्रो. (डॉ.) मणिकांत पासवान

लोंगोवाल, 24 सितम्बर (जगसीर सिंह)-

देश में अर्थव्यवस्था और व्यापारिक नीतियों को लेकर चल रहे बहसों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। इस संबंध में प्रो. (डॉ.) मणिकांत पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की आत्मनिर्भरता और मजबूत आर्थिक नीति के दम पर ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बैकफुट पर ला सकते हैं। डॉ. मणिकांत पासवान ने बताया कि हाल ही में जारी टैरिफ स्टेटमेंट और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी रक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि आर्थिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता ही देश की वैश्विक कूटनीति और व्यापारिक दबावों का सबसे मजबूत हथियार है। यही रणनीति हमें किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद में मजबूती प्रदान करती है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत ने वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की है और घरेलू उत्पादन व नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया है। यह नीति न केवल विदेशी दबाव को कम करेगी, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देगी। प्रो. मणिकांत पासवान ने यह भी कहा कि टैरिफ नीति का उद्देश्य केवल आयात-निर्यात का संतुलन नहीं, बल्कि देश की विकासशील अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना भी है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की इस रणनीति से भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की यह नीति व्यापारिक हितों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान और रणनीतिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है। इस अवसर पर प्रो. मणिकांत पासवान ने छात्रों और फैकल्टी सदस्यों से कहा कि युवाओं को भी देश की आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में योगदान देना चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक नीति वैश्विक दबावों और व्यापारिक चुनौतियों का सफल मुकाबला करेगी।

बच्चों क़े भविष्य की नींव बचपन में ही रखी जा सकती है

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर हम मनीषी जीव के अनेक रूप देखते हैं, कोई सड़क पर भीख मांग रहा है तो कोई विश्व का सबसे अमीर है !कोई स्वास्थ्यता से डैमेज होकर दिव्यांग है तो कोई विश्व कासबसे स्वस्थ व्यक्ति !कोई बच्चा फुटपाथ पर जीवन जी रहा है तो कोई महलों में है। हालांकि इस स्थिति को किस्मत का खेल भी हम मानते हैं परंतु इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि अगर एक माली या किसान जमीन में कोई बीज बोकर उसका सतर्कता से ध्यान रखना है,अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका पूरा ध्यान रखना है तो अधिकतम संभावना उसके फलदार वृक्ष बनकर आजीवन स्वस्थ उत्पादकता बनी रहती है, जिसकी नीव उसे अंकुरित बीज की देखभाल करने से पड़ी !ठीक उसी तरह अगर हम अपने बच्चों क़े स्वास्थ्य, जीवन शैली, स्वस्थ्य विकास,गुणवत्ता सुधार पर उनके बचपन से ही गंभीरता व सतर्कता से ध्यान देंगे तो उनमें गुण ही अंकुरित होते जाएंगे उनके स्वास्थ्य व स्वस्थ्य विकास के फल उनके जीवन पर्यंत मिलेंगे, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, आओ बच्चों में स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता सुधार स्वस्थ्य विकास रूपी बीज बोकर उन्हें जीवन पर्यंत स्वस्थ व फलदार वृक्ष रूपी गुणवान बनाएं।

साथियों बात अगर हमt हम बच्चों के स्वास्थ्य की करें तो ,परिवार और उनकी मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करने वालों के प्रति अपना समर्थन दिखाते हैं परिवार की आय बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख कारक है। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक बच्चों के उपचार के लिए कोई समर्पित सुविधा नहीं थी। उनका इलाज घर पर ही किया जाता था और अगर परिवारों के लिए यह विकल्प नहीहोता था , उस समय बच्चों के स्वास्थ्य की समझ को परिभाषित नहीं किया गया था और अक्सर परित्यक्त और अनाथ बच्चों को शिशु आश्रय गृहों में छोड़ दिया जाता था। अब समय के विकास के साथ बच्चों के स्वास्थ्य और गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

साथियों बात अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक बाल स्वास्थ्य एजेंडे की करें तो,पिछले दशकों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जीवित रहना वैश्विक बाल स्वास्थ्य एजेंडे का मुख्य केंद्र रहा है। परिणाम स्वरूप, 1990 और 2019 के बीच वैश्विक बाल मृत्यु दर में 60 प्रतिशत की कमी आई। 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाली 5.2 मिलियन मौतों में से कई मौतें कमज़ोर आबादी में केंद्रित थीं, विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में !इस बात के प्रमाण के आधार पर कि आजीवन स्वास्थ्य, उत्पादकता और कल्याण की नींव बचपन में ही रखी जाती है, स्वास्थ्य क्षेत्र की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चे न केवल जीवित रहें, बल्कि फलते-फूलते रहें। सतत विकास लक्ष्यों में छोटे बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं,जो मानव पूंजी उत्पन्न करता है जो हर बच्चे का अधिकार है, और न्यायसंगत और सतत प्रगति के लिए आवश्यक है। एक सुरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षात्मक वातावरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ सकें और विकसित हो सकें। बता दें 12-14 नवंबर 2024 को मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य और पोषण के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के विशेषज्ञों की 10 वीं बैठक का एजेंडा विश्व बैंक द्वारा तैयार कर लिया गया है।बचपन की बीमारियों का प्रबंधन गुणवत्तापूर्ण, बाल-केंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करके,डब्लू एचओ देशों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में काम करने में मदद करता है।उसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे अपना 10 वां जन्मदिन अच्छे स्वास्थ्य में मना सकें।स्वास्थ्य सुविधाओं में लाए गए बच्चे अक्सर एक समय में एक से अधिक स्थितियों से पीड़ित होते हैं, और पर्याप्त देखभाल प्रदान करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। कम संसाधन वाले देशों में प्रथम स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं में, रेडियोलॉजी और प्रयोगशाला सेवाओं जैसे नैदानिक समर्थन न्यूनतम या न के बराबर होते हैं, और दवाएँ और उपकरण अक्सर दुर्लभ होते हैं।इन सीमाओं के बावजूद उच्च-गुणवत्ता वाली देखभाल सुनिश्चित करने के लिए,डब्लूएचओ बचपन की बीमारी के एकीकृत प्रबंधन के निरंतर कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। निमोनिया, दस्त,मलेरिया खसरा और कुपोषण। इसके तीन घटक हैं: स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के केस प्रबंधन कौशल में सुधार, समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार, और परिवार और सामुदायिक प्रथाओं में सुधार।प्रसार वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसे 10 वर्ष तक के बच्चों तक विस्तारित करने के लिए चर्चा चल रही है।

साथियों बात अगर हम बच्चों के पालन पोषण की करें तो जिस तरह से माता, पिता और अन्य देखभालकर्ता शुरुआती वर्षों में बच्चों का पालन-पोषण और समर्थन करते हैं, वह स्वस्थ विकास और वृद्धि के लिए सबसे निर्णायक कारकों में से एक है जिसमें स्वास्थ्य, उत्पादकता और सामाजिक सामंजस्य के लिए आजीवन और अंतर-पीढ़ीगत लाभ हैं।बेहतर तरीके से बढ़ने और विकसित होने के लिए, बच्चों को पोषण संबंधी देखभाल प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि वे पर्याप्त पोषण और अच्छेस्वास्थ्य का आनंद लें, सुरक्षित और संरक्षित महसूस करें, और जन्म से ही सीखने के अवसर प्राप्त करें। बीमारी के दौरान विशेष स्तनपान, टीकाकरण और समय पर देखभाल सभी बच्चे के स्वस्थ विकास और वृद्धि में योगदान करते हैं। स्वच्छ हवा, पानी और स्वच्छता, और खेलने और मनोरंजन के लिए सुरक्षित स्थान भी छोटे बच्चों के लिए तलाशने और सीखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।जब देखभाल करने वालों को उनके देखभाल के तरीकों, परिवार, समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं में समर्थन मिलता है, तो उन्हें लाभ होता है। दूसरों की देखभाल करने के लिए उन्हें खुद को अच्छा महसूस करने की आवश्यकता होती है और इसलिए, देखभाल करने वाले के मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करना उन सेवाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो बच्चों के स्वस्थ विकास और विकास का समर्थन करती हैं।

साथियों बात अगर हम भारत में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की करें तो बच्चों सहित युवाओं का शरीर स्वस्थ तभी होगा जब उसे जरूरी मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलते रहेंगे, लेकिन आज के दौर में लगभग सभी उम्र के लोगों में अनहेल्दी फूड हैबिट्स काफी ज्यादा बढ़ गई है।शरीर के लिए पोषण की जरूरत के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है।जिस तरह इंजन को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आहार की जरूरत होती है,लेकिन शरीर स्वस्थ व निरोगी रहे, हर आयु में उसका विकास सतत रहे तथा शरीर के सभी तंत्र व प्रणालियां सही तरह से कार्य करें, इसके लिए बहुत जरूरी है शरीर को जरूरी मात्रा में पोषण मिलता रहे। लेकिन अलग-अलग कारणों से बहुत बड़ी संख्या में लोग विशेषकर बच्चे जरूरी मात्रा में पोषण ग्रहण नहीं कर पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बच्चों के भविष्य की नींव बचपन में ही रखी जा सकती है।आओ बच्चों में स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता सुधार,स्वस्थ्य विकास रूपी बीज़ बोकर उन्हें जीवन पर्यंत फलदार वृक्ष रुपी स्वस्थ्य व गुणवान बनाएं। माता- पिता व परिवार द्वारा बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली जीने में सतर्कता से ध्यान देने पर उनका पूरा जीवन सफ़लता से जीने की संभावना बढ़ती है।

जाति-मुक्त भारत की ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट क़ा ऐतिहासिक आदेश और यूपी सरकार की त्वरित पहल

जातीय व्यवस्था से भारत को मुक्ति मिलती है,तो राजनीति असली मुद्दों, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा,पर केंद्रित होगी– **एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र**

भारत में जाति व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में आज व्यापक रूप ले लिया है, और ये विवादों की सबसे बड़ी जड़ बन गई है। जातिगत पार्टियों की बहस में अब गवर्नेंस की कमी स्पष्ट होती जा रही है। चाहे यूपी हो या बिहार, कास्ट-बेस्ड पोलिटिकल पहचान डेमोक्रेसी के लिए बड़ी भीड़ जुटाती है, लेकिन शासन प्रशासन के लिए जिम्मेदारी निभाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस इलेक्शन में सभी पोलिटिकल पार्टीज को चुनौती दी जाती है कि वो कास्ट और रिलिजन से ऊपर उठकर काम करें और सबके लिए काम करने का वादा पूरा करें ।यूपी में एक बार फिर जाति के नाम पर सियासत हो रही है, लेकिन इस बार स्टाइल एकदम अलग है, हर बार जाति जानकर, जाति पूछकर राजनीतिक दल रणनीति बनाते हैं, लेकिन इस बार मामला उलट है, इस बार तो बवाल इस बात पर है कि यूपी में जाति नहीं बताई जाएगी, ना जातियों के नाम पर रैलियां होंगी, ना जाति से जुड़े नोटिस बोर्ड लगेंगे, ना पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति मेंशन होगा, ना ही वाहनों पर जाति लिखकर जोर दिखाया जाएगा, युपी सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है, यूपी सरकार को ऐसा करने के लिएइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, हालांकि सरकार ने जो आदेश जारी किया उसमें कुछ चीजें कोर्ट के बताए सुझावों से एक्स्ट्रा भी हैं, दिलचस्प ये है कि कोर्ट का ये आदेश जाति से जुड़ी किसी याचिका को लेकर नहीं आया बल्कि हुआ ये कि इटावा के जसवंत नगर थाने की पुलिस ने 29 अप्रैल, 2023 को एसयूवीं रोकी थी, जिसमें तीन लोग पकड़े गए। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की और प्रिक्रिया के होते हुए, 16 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इसने पूरे देश में नई बहस को जन्म दिया है ।अदालत ने कहा कि पुलिस दस्तावेजों, एफआईआर, अपराध रजिस्टर और सरकारी अभिलेखों में जाति का उल्लेख करना भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा) सीधे-सीधे जातिगत पहचान पर आधारित किसी भी भेदभाव को निषिद्ध करते हैं ।अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी अपराध की जांच में व्यक्ति की जाति अप्रासंगिक है और जातीय उल्लेख समाज में विभाजन को गहरा करता है। इस आदेश ने जातिवाद पर संस्थागत प्रहार किया और इसे ₹विकसित भारत 2047₹ के सपने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना गया ।इसको सफल बनाना है तो जातिवाद को समाप्त करना ही होगा। न्यायालय ने इसे केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक सुधार का हिस्सा बताया। यदि भारत अगले 22 वर्षों में जाति-मुक्त समाज बना लेता है, तो दुनियाँ के सामने यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग होगा ।इस आदेश में कहा गया है कि एससी-एसटी एक्ट जैसे मामले इस आदेश से प्रभावी नहीं होंगे ।हाईकोर्ट के आदेश के सिर्फ एक हफ्ते के भीतर 23 सितंबर 2025 को यूपी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शासनादेश जारी किया। इस आदेश के तहत निर्देश दिया गया कि अब से पुलिस अभिलेखों,सरकारी रजिस्टरों और प्रशासनिक फाइलों में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार ने सभी विभागों को यह भी आदेश दिया कि जातीय पहचान को दर्ज करने की प्रथा समाप्त की जाए ।यूपी सरकार ने इस कदम को सामाजिक समरसता और ₹सबका साथ, सबका विकास₹ की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। इसे जातिवाद समाप्त करने कीराजनीतिक इच्छाशक्ति का उदाहरण माना गया ।इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगेजाति-मुक्त भारत की ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट क़ा ऐतिहासिक आदेश और यूपी सरकार की पहल।

साथियों बात अगर हम भारत के लिए यूपी मॉडल, एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला होने की करें तो यूपी, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, अक्सर राजनीतिक और सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला माना जाता है। यदि यहाँ जातीय उल्लेख को समाप्त करने की नीति सफल होती है, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकती है। 2047 तक विकसित भारत के विजन को सफल बनाने के लिए इस पहल को ₹मील का पत्थर₹ कहा जा रहा है। सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि जाति को प्रशासनिक दस्तावेजों से हटाया गया तो धीरे-धीरे यह चुनावी राजनीति और सामाजिक व्यवहार से भी कमज़ोर होगी ।जातीय राजनीति पर विराम लगेगा और लोकतंत्र की नई दिशा मिलेगी, भारत की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। प्रत्याशी चयन, टिकट वितरण, गठबंधन और चुनावी रणनीति सब जाति के अंकगणित पर टिकी रहती हैं। यदि प्रशासनिक स्तरपर जाति का उल्लेख ही नहीं होगा, तो धीरे-धीरे जातीय पहचान की राजनीतिक महत्ता घटेगी। इससे लोकतंत्र अधिक विचार-आधारित और विकास- आधारित हो सकेगा। जातिवाद पर यह प्रहार भारतीय लोकतंत्र को उसकी मूल आत्मा, ₹एक व्यक्ति, एक वोट₹, के असली स्वरूप के बहुत सटीक करीब ले जाएगा।

साथियों बात अगर हम क्या भारत में जाति-मुक्त समाज संभव है? इस प्रश्नों को समझने की करें तो,सवाल उठता है कि क्या भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश जाति-मुक्त समाज बना सकता है? उत्तर यह है कि कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। जाति-मुक्त समाज बनने से निम्नलिखित फायदे होंगे(1) सामाजिक समानता- कोई ऊँच-नीच नहीं, सबको समान सम्मान। (2) आर्थिक अवसरों की समानता-रोजगार और शिक्षा में अवसर जाति से नहीं, क्षमता से तय होंगे। (3) राजनीतिक स्थिरता-जातीय संघर्ष और वोट-बैंक कीराजनीति कम होगी।(4)राष्ट्रीय एकता- जाति-धर्म की दीवारें गिरने से भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी ।जाति-आधारित राजनीति खत्म करने की आवश्यकता-जाति-आधारित राजनीति ने भारत में कई बार समाज को विभाजित किया है। यदि राजनीतिक पार्टियाँ जातीय समीकरणों पर टिकट देना बंद करें और केवल योग्यता, सेवा और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ें तो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। समाज में झगड़े-झमेले घटेंगे और राष्ट्रीय ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में तेज़ी से लगेगी।

साथियों बात अगर हम एमवाय और पीडीए की राजनीति विभाजन की जड़ और लोकतंत्र में आंकड़ों के खेल को समझने की करें तो, भारतीय राजनीति में एमवाय (मुस्लिम-यादव) और पीडीए (पिछड़ा-दलित- अल्पसंख्यक) समीकरणों ने दशकों तक पार्टियों की चुनावी रणनीति तय की। इससे जाति और धर्म को एक स्थायी राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया। यदि जातीय व्यवस्था से भारत को मुक्ति मिलती है, तो ये समीकरण अप्रासंगिक हो जाएंगे और राजनीति असली मुद्दों, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा,पर केंद्रित होगी।लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल- जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और समाज क़ा वेटज़-भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अक्सर चुनावों को जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर बांट दिया जाता है। किसी समुदाय की जनसंख्या का ₹वेटेज₹ जितना अधिक होता है, राजनीतिक पार्टियाँ उतनी ही उसकी परवाह करती हैं। यही कारण है कि हर पार्टी का चुनावी रोडमैप जातीय समीकरणों पर आधारित होता है। लेकिन यदि जातीय उल्लेख बंद हो जाएगा, तो धीरे-धीरे यह वेटेज अप्रासंगिक होगा और लोकतंत्र वास्तविक रूप से जन-केन्द्रित बनेगा।

साथियों बातें अगर हम जाति समीकरणों के इतिहास को समझने की करें तो, 1950 से 1990 तक जातीय राजनीति का विकास भारत की आज़ादी के बाद राजनीति में जातीय समीकरण धीरे-धीरे हावी होते गए।(1)1950-1970-इस दौर में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम राजनीति के केंद्र में रहे। कांग्रेस ने इन्हें संतुलित करने की कोशिश की।(2)1974-पिछड़ी जातियों के नेताओं का उदय शुरू हुआ, जिसने राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण बदल दिया। (3)1990-मंडल आयोग, पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के फैसले ने जातीय राजनीति को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। इसके बाद से हर चुनाव जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमने लगा।

यूरोपीय देशों के समर्थन से फिलिस्तीन को क्या मिला

राजेश कुमार पासी

ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय देशों में फिलिस्तीन को मान्यता देने की होड़ लग गई है. एक-एक करके कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है । कुछ दिनों के अंदर ही कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, मोनाको, माल्टा, लक्जमबर्ग और बेल्जियम ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। जहां इसका फिलिस्तीन अधिकारियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है तो इजराइल ने इसका जबरदस्त विरोध किया है। लगभग 150 देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। यूरोपीय देशों पर अमेरिका का जबरदस्त दबाव था कि वो ऐसा कदम न उठाएं लेकिन अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए इन देशों से फिलिस्तीन को मान्यता दी है। सवाल यह है कि जब 140 देशों ने फिलिस्तीन को पहले ही मान्यता दे रखी थी तो अब इन देशों द्वारा मान्यता मिलने से क्या होने वाला है । अगर अमेरिका फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता है तो फिलिस्तीन को कोई फायदा होने वाला नहीं है । अमेरिकी विरोध के कारण उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूर्ण देश का दर्जा नहीं मिलेगा। अमेरिका का दोगलापन इस बात से समझा जा सकता है कि उसने सीरिया के राष्ट्रपति जुलानी को अमेरिका का वीजा दे दिया जबकि वो एक खतरनाक वांछित आतंकवादी रह चुका है जिस पर अमेरिका ने ही दस मिलियन डॉलर का इनाम रखा हुआ था । दूसरी तरफ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया है जबकि उनके ऊपर किसी भी आतंकवादी कार्यवाही में भाग लेने का आरोप नहीं है । सवाल उन देशों से भी है, जो फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं जबकि कई ऐसे देश हैं जो अभी भी मान्यता देने के लिए गुहार लगा रहे हैं । अफ्रीकन यूनियन के दबाव के कारण सोमालीलैंड को ज्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी है । चीन की ताकत को देखते हुए दुनिया के लगभग सारे देश वन चाइना नीति को मान्यता देते हैं, इसलिए ताइवान को कोई भी मान्यता देने को तैयार नहीं है । कोसोवो को सिर्फ सौ देशों ने ही मान्यता दी है । सवाल यह है कि जो यूरोपीय देश अभी तक अमेरिकी दबाव के कारण फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे रहे थे, वो अब मान्यता क्यों दे रहे हैं ।

इसकी कई वजह हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कारण यूरोपीय देश अमेरिका से टकराव के मूड में हैं । ट्रंप टैरिफ के नाम पर यूरोपीय देशों को धमका चुके हैं और दबाव डालकर यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील पर साइन करवा लिए हैं । यूरोपीय देश अरब देशों सहित अन्य मुस्लिम देशों से संबंध सुधारना चाहते हैं । कई यूरोपीय देशों में वामपंथी विचारधारा से प्रेरित दलों की सरकार चल रही है जो फिलिस्तीन के हमदर्द हैं । यूरोपीय देशों में मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है. उनको खुश करने के चक्कर में भी यह कदम उठाया जा रहा है । यूरोपीय देश क्या सोचते हैं, ये उनकी समझ हो सकती है लेकिन इससे फायदा होने की जगह नुकसान होने का ज्यादा अंदेशा है । उनके इस कदम से कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ने वाला है । इसकी बड़ी कीमत यूरोपीय देशों को चुकानी होगी । ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना गलत है लेकिन उनकी मंशा अच्छी नहीं है । गलत मंशा से उठाया गया सही कदम भी नुकसान पहुंचाता है । कट्टरपंथी इसे अपनी जीत मानकर इन देशों पर इजराइल से रिश्ते तोड़ने का दबाव बनाएंगे जिसको मानना इतना आसान नहीं होगा ।

यूरोपीय देशों में इजराइल के विरोध में हिंसक प्रदर्शन नए सिरे से शुरू हो सकते हैं । उनके लिए फिलिस्तीन कोई मुद्दा है ही नहीं, उनका असली मुद्दा कट्टरपंथ बढ़ाना है । इटली में फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंसक प्रदर्शन किया है । प्रदर्शनकारियों ने सरकारी और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है । सवाल यह है कि फिलिस्तीन के समर्थन में ये लोग उन देशों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, जो इन्हें अपना नागरिक मानते हैं । जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, उन्हें फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास की बात भी सुननी चाहिए । अब्बास ने कहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला एक घिनौनी आतंकवादी हरकत थी । उनका कहना है कि उन आतंकवादियों का गाजा पर कोई अधिकार नहीं है । जो लोग आज फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वही लोग हमास का भी समर्थन कर रहे थे । कतर ने हमास के नेताओं को अपने देश में शरण दे रखी है, वो लोग वहां रहकर ही इजराइल में आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं । जो लोग यूरोपीय देशों में रैलियां निकालकर फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं, वो लोग क्या हमास को आतंकवादी संगठन मानने को तैयार हैं । इन लोगों ने क्या कभी हमास के आतंकवादी हमले के विरोध में रैली निकाली है । वास्तव में फिलिस्तीन के नाम पर यूरोपीय देशों में कुछ संगठन इस्लामिक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं ।

मान्यता देने वाले देशों का कहना है कि इजराइल-फिलिस्तीन समस्या का समाधान द्वि-राष्ट्र सिद्धांत हैं लेकिन सवाल यह है कि इस सिद्धांत को तो इजराइल के गठन के समय भी माना गया था । तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इस सिद्धांत को मानने से इंकार कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि इजराइल दुनिया में होना ही नहीं चाहिए । तब उनका कहना था कि फिलिस्तीन पर सिर्फ फिलिस्तीनियों का हक है । 1948 में इजराइल बनने के दूसरे ही दिन उसको समाप्त करने के लिए पांच अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया था । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने फिलिस्तीन को दो देशों में विभाजित करके इजराइल को एक नया देश बनाया था । इजराइल के हिस्से 56 प्रतिशत और फिलिस्तीन के हिस्से में 44 प्रतिशत भूमि आई थी । 1948 के युद्ध के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया । देखा जाये तो द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की अवहेलना पहले अरब देशों द्वारा ही की गई थी । फिलिस्तीन को अपनी जमीन इसलिए गवांनी पड़ी क्योंकि अरब देशों ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को नकार कर इजराइल को खत्म करने की कोशिश की थी ।

सवाल यह है कि अगर इजराइल युद्ध हार जाता तो क्या आज इजराइल का अस्तित्व होता । इसके बाद 1967 में तीन अरब देशों ने फिर इजराइल पर हमला कर दिया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी । इसके बाद इजराइल ने फिर फिलिस्तीन की कुछ भूमि अपने कब्जे में ले ली । भारत ने पाकिस्तान की कब्जा की गई भूमि वापिस की लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान भारत की भूमि पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता तो क्या वो कब्जा की गई भूमि वापिस करता । पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अमेरिका का समर्थन हासिल था । इजराइल के साथ ऐसा नहीं था. जब उसने फिलिस्तीन की भूमि कब्जा की तो उसने वापिस नहीं की क्योंकि अमेरिका उसके पीछे खड़ा था और आज भी खड़ा है। जब तक अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते, कुछ होने वाला नहीं है। अमेरिका भी अगर फिलिस्तीन का समर्थन कर देता है तो भी इजराइल नहीं मानने वाला क्योंकि वो अमेरिका की बात एक सीमा तक सुनता है और फिर अपनी मर्जी चलाता है।

इजराइल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं बचा है । इसकी वजह यह है कि वेस्ट बैंक पर इजराइल का पूरा नियंत्रण है और गाजा को वो पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर चुका है । देखा जाए तो जमीन पर फिलिस्तीन कहीं दिखाई नहीं देता है । ऐसा करने का मौका फिलिस्तीन समर्थक मुस्लिम देशों ने ही इजराइल को दिया है । इजराइल ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था और वो अपने विकास में लग गया था लेकिन उसे समाप्त करने की मुस्लिम देशों की जिद्द ने हालात बिगाड़ दिए । आज वही देश द्वि-राष्ट्र सिद्धांत अपनाने की बात करते हैं । जिस राष्ट्र को इजराइल लगभग निगल चुका है, वो अब कैसे अस्तित्व में आएगा । फिलिस्तीनी इजराइल को दुनिया से खत्म कर देना चाहते हैं और इस काम में वो लगातार लगे हुए हैं । आतंकवाद को हथियार बनाकर वो इजराइल को समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कई मुस्लिम देश इसमें उनकी मदद कर रहे हैं । इजराइल अपनी ताकत से इनके खिलाफ लड़ रहा है । इजराइल जानता है कि दुनिया उस पर रहम करने वाली नहीं है, उसे अपनी ताकत से ही जिंदा रहना होगा।

भारत ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार कर लिया लेकिन क्या पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया । पाकिस्तान ने इसे कभी नहीं स्वीकार किया. वो अस्तित्व में आने के बाद से ही भारत पर कब्जा करने की फिराक में है । अपनी इस कोशिश में ही वो भारत से चार युद्ध लड़ चुका है । जब उसने देखा कि वो भारत से युद्ध में जीत नहीं सकता तो उसने आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को खत्म करने की साजिश की । दुनिया को समझना होगा कि वास्तविक मुद्दा फिलिस्तीन नहीं बल्कि इजराइल है जिसे किसी भी तरह खत्म करना है । फिलिस्तीनियों के साथ कितनी भी सहानुभूति जताई जाए लेकिन सच यह है कि ये लोग इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । अगर फिलिस्तीनी इजराइल के साथ रहना सीख जाते तो आज ये हालात न होते । गाजा में जो हो रहा है, वो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता लेकिन हमास का समर्थन इन्हीं गाजावासियों ने किया था । जब तक दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी नहीं होती, तब तक गाजा बनते रहेंगे । आतंकवाद का समर्थन करना कितना भारी पड़ता है, ये हमें गाजा बता रहा है । सवाल यह है कि क्या दुनिया इस सबक को सीखने को तैयार है । जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होता, तब तक फिलिस्तीन को मान्यता देकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है ।

राहुल का वार, संघ से तकरार और वैश्विक दबावों में मोदी सरकार

ओंकारेश्वर पांडेय

एक तरफ राहुल गांधी का वार, दूसरी तरफ संघ से तकरार, इधर ट्रंप का टैरिफ वार तो उधर चीन फायदा उठाने पर सवार, उम्र हो गई 75 पार और समस्याओं का बढ़ता अंबार, यह पंक्ति कोई कविता नहीं, बल्कि 2025 के भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक सच्चाई बन चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के ठीक अगले दिन, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर "केंद्रीकृत वोट चोरी ऑपरेशन" का आरोप लगाकर लोकतंत्र की नींव को चुनौती दी लेकिन यह हमला सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं था—यह उस सत्ता संरचना पर था जो अब हर मोर्चे पर दबाव में है।

अगला हमला राष्ट्रपति ट्रंप ने किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए एच-1बी वीजा (H-1B Visa) के लिए नई शर्तें लागू कर दी हैं. अब इस वीजा को हासिल करने के लिए कंपनियों को हर साल 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) की फीस चुकानी होगी. इस फैसले से लाखों विदेशी पेशेवरों पर असर पड़ सकता है, खासकर भारतीय आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर, जो अमेरिका के एच-1बी वीजा पर सबसे ज्यादा निर्भर है.

राहुल गांधी का वार: दस्तावेज़ों से लोकतंत्र की रक्षा

18 सितम्बर 2025 को राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक योजनाबद्ध ऑपरेशन को संरक्षण दिया जिससे कांग्रेस के मजबूत बूथों पर वोट डिलीट किए गए। उन्होंने कर्नाटक CID की जांच का हवाला देते हुए बताया कि आयोग को 18 महीनों में 18 बार तकनीकी जानकारी मांगी गई—IP एड्रेस, OTP ट्रेल्स, डिवाइस पोर्ट्स—लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

राहुल ने कहा कि "अगर ये डेटा दिया जाता, तो ऑपरेशन चलाने वाले तक सीधा पहुंचा जा सकता था।" उन्होंने गोदाबाई, सूर्याकांत और नागराज जैसे मामलों को उदाहरण के तौर पर रखा, और इसे "मानव रूप से असंभव" बताया।

बेंगलुरु से बिहार तक: राहुल गांधी की रणनीति का विस्तार

इस हमले की शुरुआत जुलाई 2025 में बेंगलुरु में हुई "एटम बम प्रेस कॉन्फ्रेंस" से हुई थी जब उन्होंने महादेवपुरा क्षेत्र में एक लाख से अधिक वोटों की कथित डिलीशन का खुलासा किया। इसके बाद बिहार में 17 दिन की "वोट अधिकार यात्रा" में उन्होंने दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के वोटों को योजनाबद्ध तरीके से हटाने का आरोप लगाया।

बिहार में Special Intensive Revision (SIR) को आनन फानन कराया ही यह कहकर किया गया था कि राज्य में बड़े पैमाने पर नेपाली, म्यांमारी और बांग्लादेशी घुसपैठिये भर गये हैं, उनका नाम हटाना जरुरी है।

लेकिन इसके तहत हुए मतदाता पुनरीक्षण में मतदाताओं की संख्या 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ मतदाता रह गयी—यानि 66 लाख वोटों की कटौती लेकिन Election Commission of India के डिलीटेड नामों में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं था।

विपक्ष ने वाजिब सवाल उठाया: "अगर वोटर को आधार के बिना डिलीट किया जा सकता है तो घुसपैठियों को क्यों नहीं हटाया जा सकता?"

असम से लेकर दिल्ली तक भाजपा सरकार सत्ता में है। बांग्लादेशी मुद्दा भाजपा का कोर मुद्दा रहा है। इसलिए बांग्लादेशियों को भगाने के लिए सरकार ने क्या किया, यह जाना जरुरी है। तो आइये देखते हैं।

विदेशी घुसपैठ: आंकड़ों की चतुराई और सच्चाई

Organiser की रिपोर्ट में कहा गया कि असम में कुल 1,65,531 लोगों को "अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया" घोषित किया गया और 30,115 को निष्कासित किया गया। लेकिन गौर से पढिए - यह आंकड़ा 1966 से 2024 तक का संयुक्त डेटा है जिसमें कांग्रेस सरकारों का कार्यकाल भी शामिल है। BJP सरकार के 10 वर्षों में कितने निष्कासित हुए, इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

आंकड़ों के मुताबिक 2024–25 में ही 2,300 से अधिक लोगों को "घुसपैठिया" घोषित किया गया लेकिन सिर्फ 312 को ही न्यायिक प्रक्रिया के बाद निष्कासित किया गया। यह निष्कासन दर मात्र 13.5% रही।

ध्यान रहे 2,300 से अधिक लोगों को "घुसपैठिया" घोषित किया गया लेकिन सिर्फ 312 को ही निष्कासित किया गया।

अब असम के सुपर एक्टिव मख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मई 2025 में क्या कहा, सुनिए : "We have adopted a push-back policy for undocumented immigrants."

ये पुश बैक पॉलिसी है, डिटेक्ट एंड डिपोर्ट पॉलिसी नहीं। जाहिर है कि असम की बीजेपी सरकार घुसपैठियों को लेकर केवल वही कर रही है जो काम दशकों से बीएसएफ सामान्य ड्यूटी के रूप में करते हैं।

लेकिन हिमंत बिस्वा सरमा सरकार के पुश बैक प्लान को भी Amnesty International ने इसे "due process का violation" करार देकर झटका दे दिया है।

अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में NDA की सरकार लगभग 20 वर्षों से है लेकिन घुसपैठियों की पहचान और निष्कासन पर कोई ठोस आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया।

BSF के आंकड़े: सीमा पर सच्चाई

BSF के अनुसार, 2023 में 2,406, 2024 में 2,425, और 2025 में मई तक 557 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हुए पकड़ा गया और वापस भेजा गया। लेकिन राज्यवार आंकड़े बताते हैं कि:

- पश्चिम बंगाल में 2,688 मामले सामने आए।

यानी जिस ममता बनर्जी की सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने के आरोप लगाये जाते हैं, उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा बाग्लादेशी घुसपैठिये निकाले गए।

मिज़ोरम में भी 1,679 और त्रिपुरा में 771 बाग्लादेशी घुसपैठिये निकाले गए लेकिन असम में सिर्फ 51 लोगों को वापस भेजा गया वह भी तीन वर्षों में।

कुल मिला कर देखा जाय तो BJP-शासित असम में घुसपैठ की पहचान और निष्कासन सबसे कम रहा।

इस बीच Border Guard Bangladesh (BGB) ने कई बार भारत द्वारा "पुश-बैक" की कोशिशों का विरोध किया है। उदाहरण के लिए - मई 2025 में 13 लोग Zero Line पर फंसे रहे जिन्हें न भारत ने वापस लिया, न बांग्लादेश ने स्वीकार किया।

विदेश नीति: गुटनिरपेक्षता से भ्रम की ओर

मनमोहन सरकार की विदेश नीति संतुलन पर आधारित थी लेकिन मोदी सरकार ने QUAD, BRICS और रूस-यूक्रेन युद्ध में सक्रिय भूमिका लेकर भारत की पारंपरिक स्थिति को बदल दिया।

- QUAD में शामिल होकर चीन को नाराज़ किया

- BRICS में रहते हुए रूस से तेल खरीदकर पश्चिमी देशों से टकराव बढ़ाया

- अमेरिका से रिश्ते बिगड़े, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा:

"India and Pakistan were on the brink of war. I stopped it."

- ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकडियों और बेड़ियों में भारत भेजा।

- पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ छेड़े गये आपरेशन सिंदूर को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार रोकने की धमकी देकर रुकवा दिया। और यहाँ तक कि भारत को शर्मसार करते हुए यह बयान उन्होंने 50 से अधिक बार दोहराया।

इसके बाद अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल और फार्मा उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया। फिर रुस से तेल खरीदने के कारण 25 फीसदी का दंडात्मक टैक्स लगाया।

मजबूरन मोदी उस चीन के पास गये जो दो महीने पहले पाकिस्तान के साथ युद्ध में हथियार, विमान और मिसाइलों के अलावा सीधे टैक्टिकल सपोर्ट भी दे रहा था। भारतीय सेना ने कहा कि हम दो मोर्चे पर लड़ रहे थे। अमेरिका के दबाव में आये मोदी फिर बिना सोचे समझे चीन के पास सहारे के लिए गए पर चीन ने उनका फायदा उठाया। चीन ने भारत को तीन नए बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स खोलने पर सहमत करा लिया जबकि भारत का चीन से व्यापार घाटा $99.2 बिलियन तक पहुँच गया है। यह एक तरह से ट्रंप और जिनपिंग के बीच सैंडविच बनने जैसा है।

आर्थिक दबाव: बढ़ता कर्ज और गिरती FDI

इधर देश पर विदेशी कर्ज का दबाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। 2014 में भारत का विदेशी कर्ज लगभग ₹55 लाख करोड़ था। 2025 में यह बढ़कर ₹220 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। विदेशी कर्ज का GDP अनुपात 19.1% तक पहुँच गया है।

कर्ज कम लेना पड़ता, अगर हमारा विदेशी निवेश अपनी उसी रफ्तार से बढ़ता जो डॉ मनमोहन सिंह के सरकार में था। दुर्भाग्य से FDI के मोर्चे पर भारी गिरावट आई है:

- 2014: $45 बिलियन
- 2020: $64.36 बिलियन
- 2023: $28.08 बिलियन
- 2025: $17 बिलियन से नीचे

यह गिरावट भारत की नीति स्थिरता पर निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है। नकली डंका बजाने से असली मुद्रा नहीं आती। FDI के मोर्चे पर आई गिरावट ही हमारे देश में नौकरियां पैदा करने में सबसे बड़ी बाधा है।

संघ की समझ और सत्ता की चुप्पी

RSS अब भी हालात को नहीं समझ सका है। मुरली मनोहर जोशी की 70 स्लाइड्स की प्रस्तुति में भारत की आर्थिक गिरावट पर चिंता तो जताई गई पर बहुत से मुद्दों से वे अनभिज्ञ लगते हैं। मोदी खेमा इस बात से ज्यादा दुःखी है कि मुरली मनोहर जोशी के प्रेजेंटेशन में वामपंथी नोबल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन का हवाला क्यों दिया गया।

2025 का भारत अब सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रहा—यह लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और कूटनीति की त्रिकोणीय लड़ाई है। एक तरफ राहुल गांधी हर बार एक नई गाँठ बाँधते हैं, और दूसरी तरफ सरकार हर बार एक नई गलती करती है।

मोदी को अपनी आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक कूटनीतिक चूकों का कोई अहसास नहीं है। गोदी मीडिया उनकी हर हार को जीत, हर नुकसान को फायदा, और हर तमाचे को मास्टर स्ट्रोक बताकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अंधभक्तों ने उनको भी अंधा बना दिया है, और उधर ही ले जा रहे हैं, जहाँ गहरी खाई है। मोदी उस खाई में गिरे, तो भी ये गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक का ब्रेकिंग चलाएगा, ये तय है।

मोदी सरकार को अब कोई गिला विपक्ष से रखने की वजह नहीं है। विपक्ष तो सवाल पूछ रहा है, दस्तावेज़ ला रहा है, जनभावना को स्वर दे रहा है। गिला उन सलाहकारों से है जिसने नीति को भ्रम बना दिया, अर्थव्यवस्था को कर्ज में डुबो दिया और विदेश नीति को अस्थिरता के गहरे भंवर में फंसा दिया।

ओंकारेश्वर पांडेय
लेखक अनुभवी वरिष्ठ संपादक एवं रणनीतिकार हैं।

एक राष्ट्र, एक चुनाव: एकजुट भविष्य की ओर

जयसिंह रावत

दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां 90 करोड़ से अधिक मतदाता एक अरब से ज्यादा लोगों के भाग्य का निर्धारण करते हैं, चुनावों की लय अब तक अलग-अलग अभियानों, निरंतर व्यय और शासन में रुकावटों से भरी रही है। अब ₹एक राष्ट्र, एक चुनाव₹ (ONOE) की अवधारणा सामने आई है—यह एक साहसिक दृष्टिकोण है जो चुनावी कैलेंडर को सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयास करता है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव हर पांच साल में एक साथ कराए जाएंगे। समर्थक इसे दक्षता और वित्तीय समझदारी की वापसी मानते हैं, जबकि यह भारत की संघीय संरचना को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर भी है। जैसे-जैसे यह प्रस्ताव संवैधानिक बहसों के बीच गति पकड़ रहा है, यह उचित होगा कि हम राष्ट्र की पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया की याद करें—एक ऐसा अद्भुत प्रयास जिसने एक व्यक्ति के नेतृत्व में सब कुछ संभव कर दिखाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी।

भारतीय लोकतंत्र का उदय: सुकुमार सेन का ऐतिहासिक योगदान

स्वतंत्र भारत का मतदान से अभिषेक एक छोटी दौड़ नहीं, बल्कि चार महीनों तक चलने वाला एक लंबा संघर्ष था, जो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। यह पहला आम चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं था; यह एक नवजात गणतंत्र के लिए स्वशासन का साहसिक प्रयोग था, जो विभाजन की हिंसा, शरणार्थी संकट और व्यापक अशिक्षा से जूझ रहा था। 1.73 लाख से अधिक मतदान केंद्रों ने पूरे देश में फैले 17.3 करोड़ से ज्यादा पात्र मतदाताओं की सेवा की—उस समय दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा। मतपत्रों पर प्रतीकों की बजाय शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जहां साक्षरता दर 20 प्रतिशत से कम थी, वहां समझ की सीमाओं को चुनौती दी गई। इस महान कार्य के केंद्र में थे सुकुमार सेन, एक शांत स्वभाव वाले बंगाली सिविल सेवक, जिन्हें 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया। कोई पूर्व योजना या बड़ी नौकरशाही के बिना, सेन ने इस विशालकाय कार्य को अकेले संभाला, 3 लाख से अधिक अधिकारियों की भर्ती की, पोस्टरों और लोक गीतों के माध्यम से मतदाता शिक्षा का नवाचार किया, और धोखाधड़ी रोकने के लिए मतपत्र डिजाइन को मानकीकृत किया। सांप्रदायिक तनावों और दूरदराज इलाकों में हाथियों से मतपत्र पहुंचाने जैसी चुनौतियों के बीच, सेन की दृढ़ता ने संभावित अराजकता को विजय में बदल दिया। कांग्रेस पार्टी ने 489 में से 364 सीटें जीतीं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, 51 प्रतिशत मतदान ने अज्ञात में विश्वास की पुष्टि की: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सेन ने इसे ₹विश्वास का कार्य₹ कहा, एक ऐसा वाक्यांश जो उस युग की जोखिम भरी आशावादिता को दर्शाता है। उनका योगदान? एक मजबूत चुनाव आयोग, जो अब तक 17 लोकसभा चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर चुका है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी लोकतंत्र की मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने की क्षमता साबित करता है।

उल्लेखनीय रूप से, यह पहला मतदान अलग-थलग नहीं था; राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ चले, जिसने 1967 तक चार चक्रों में एक साथ चुनाव की परंपरा को जन्म दिया। यह एक एकजुट लय थी, जो निरंतर चुनावी अभियानों से अछूती रही।

एकजुटता की वापसी की आवश्यकता

1960 के दशक के अंत में यह सामंजस्य टूट गया, समय से पहले सरकारों के भंग होने और अलग-अलग कार्यकालों के कारण—भारत के अस्थिर संसदीय जीवन की विशेषता। इंदिरा गांधी के 1971 के मध्यावधि चुनावों और राज्य स्तर की उथल-पुथल ने कैलेंडर को बिखेर दिया। आज, 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यकालों के असंतुलन के साथ, भारत एक साल में सात बड़े चुनावों का सामना करता है, साथ में उप-चुनाव और स्थानीय मतदान। वित्तीय बोझ? सरकारी अनुमानों के अनुसार, पांच वर्षों में 4.5 लाख करोड़ रुपये (लगभग 54 अरब डॉलर), जो विकास कोष से निकाले जाते हैं। पैसे से परे, ₹आदर्श आचार संहिता₹ महीनों तक नीति निर्णयों को रोक देती है, अधिकारियों को कर्तव्यों से हटाती है और अभियान निधियों के माध्यम से काले धन के प्रवाह को बढ़ावा देती है। यह विचलन आवश्यकता से जन्मा था, लेकिन अब यह अक्षमता में बदल गया है। ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' न केवल एक पुनरुद्धार है, बल्कि एक प्रगतिशील कदम जो इन चुनौतियों को दूर करने का वादा करता है।

समिति, विधेयक और संवैधानिक प्रगति

यह विचार दशकों से उबल रहा था—1983 में चुनाव आयोग और 2017 में नीति आयोग द्वारा समर्थित—फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2023 में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित कर इसे औपचारिक रूप दिया। पैनल की मार्च 2024 की रिपोर्ट ने चरणबद्ध रोलआउट की वकालत की: 2029 तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को संरेखित करना, फिर 2034 तक पंचायत और नगरपालिका चुनावों को शामिल करना। इसमें संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन का प्रस्ताव है, कार्यकाल को पांच वर्षों पर तय करना, समय से पहले भंग होने पर ₹नए चुनाव₹, और डुप्लिकेशन कम करने के लिए एकल मतदाता सूची। दिसंबर 2024 में, दो विधेयक—संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक—संसद में पेश किए गए, जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देते हैं, लेकिन सेन के युग की तरह: चुनावों को राष्ट्रीय एकजुटता के रूप में देखना। दो-तिहाई बहुमत और राज्य अनुमोदन की आवश्यकता के साथ, ये विधेयक एक प्रेरणादायक दिशा दिखाते हैं।

दक्षता और विकास की नई सीमा

समर्थक एक राष्ट्र एक चुनाव को केवल पुरानी याद नहीं मानते; यह व्यावहारिक विकास है। वित्तीय रूप से, यह व्यय को 40-50% तक कम कर सकता है, बचत को बुनियादी ढांचे और कल्याण पर पुनर्निर्देशित कर सकता है—एक ऐसे राष्ट्र में महत्वपूर्ण जहां चुनावी लागत रक्षा बजट से प्रतिस्पर्धा करती है। शासन को भी गति मिलती है: कम रुकावटें मतलब निर्बाध नीति फोकस, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है और ₹चुनाव लाभांश₹ के हैंगओवर को कम कर सकता है। मतदाता थकान, एक और समस्या, एकीकृत अभियानों से कम हो सकती है, जैसा कि इतिहास में एक साथ चुनावों में उच्च मतदान (जैसे 2019 में 67 प्रतिशत बनाम विभिन्न राज्य औसत) से साबित होता है। वैश्विक रूप से, स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका सिंक्रोनाइज्ड चक्रों पर फलते-फूलते हैं, जो सुझाव देते हैं कि भारत सुव्यवस्थित लोकतंत्रों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। विचारोत्तेजक प्रश्न यह है कि डिज़िटिलाइजेशन के युग में, क्या ₹एक राष्ट्र, एक चुनाव₹ नागरिकों की आवाजों को मजबूत कर सकता है और लोकतंत्र को और अधिक प्रभावी बना सकता है? इसके अलावा, यह सेन के योगदान की सराहना करता है, जो एकजुट चुनावों की परंपरा को पुनर्जीवित कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, विकास को प्राथमिकता देता है और मतदाताओं को सशक्त बनाता है।

संघवाद को मजबूत करने की चुनौतियां

हालांकि कुछ आलोचक स्थिर कार्यकालों से राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव की चिंता करते हैं, लेकिन ₹एक राष्ट्र, एक चुनाव₹ वास्तव में संघीय संरचना को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है, जहां राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को एक साथ संबोधित किया जा सकता है। लॉजिस्टिकली, 28 राज्यों को संरेखित करना एक चुनौती है, लेकिन अधिक ईवीएम, कर्मचारी और सुरक्षा के साथ, भारत की विविधता को सम्मान देते हुए इसे हासिल किया जा सकता है। यह एक बहुलवादी राजनीति को समृद्ध कर सकता है, जहां क्षेत्रीय दल गठबंधन में मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। आपात स्थितियों में, मध्यावधि पतन को प्रबंधित करने के प्रावधान स्थिरता सुनिश्चित करेंगे।

गणतंत्र के लिए एक मोड़

जैसे-जैसे विधेयक संसदीय प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, ₹एक राष्ट्र, एक चुनाव₹ हमें सोचने पर मजबूर करता है: सुकुमार सेन ने केवल चुनाव नहीं चलाया; उन्होंने एक चमत्कार को जन्म दिया, जो विपरीतता में एकता की संभावना साबित करता है। आज का प्रस्ताव, तकनीकी रूप से मजबूत, उसी भावना से जुड़ा है—स्केल और आत्मा का संतुलन। यह 1952 की सिंक्रोनाइज्ड लय को पुनर्जीवित कर सकता है, एक दुबला, मजबूत लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकता है। ₹एक राष्ट्र, एक चुनाव₹ चुनावों से परे है; यह भारत की आकांक्षाओं पर एक जनमत संग्रह है। सेन के ₹विश्वास के कार्य₹ में हम संभावना देखते हैं: एक राष्ट्र जो एक साथ वोट करता है, न कि अलग-अलग गूंजों में। लेकिन उस पहले मतपत्र की तरह, सफलता समावेशिता पर निर्भर है। मतदाता—वे 10 करोड़ पथप्रदर्शक और उनके वंशज—इससे अधिक के हकदार हैं। भारत का लोकतंत्र आगे किस लय पर नाचेगा? मतपेटी, हमेशा की तरह निर्णयकर्ता, इंतजार कर रही है।

अनुभवजन्य मानविकी की आवश्यकता

विजय गर्ग

अनुभवजन्य मानविकी की आवश्यकता गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के बीच पारंपरिक अंतर को पाटने की इच्छा से उपजी है, जिससे मानव स्थिति के अधिक मजबूत, डेटा-संचालित और प्रभावशाली अध्ययन की अनुमति मिलती है। जबकि मानविकी ने ऐतिहासिक रूप से ग्रंथों, कलाकृतियों और विचारों के व्याख्यात्मक और सैद्धांतिक विश्लेषण पर भरोसा किया है, एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण इन विषयों के लिए अवलोकन, माप और डेटा विश्लेषण जैसे वैज्ञानिक तरीकों को लागू करना चाहता है। यहाँ अनुभवजन्य मानविकी के लिए धक्का के पीछे प्रमुख कारणों और तरीकों का टूटना हैः 1.। मानविकी अनुसंधान की कठोरता और विश्वसनीयता को बढ़ाना

पूरक पद्धतियांः पारंपरिक मानविकी विधियों को बदलने के बजाय, अनुभवजन्य दृष्टिकोण एक शक्तिशाली पूरक के रूप में काम करते हैं। उनका उपयोग परिकल्पनाओं का परीक्षण करने, पैमाने पर पैटर्न की पहचान करने और मात्रात्मक डेटा के साथ गुणात्मक निष्कर्षों को मान्य करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक साहित्यिक विद्वान उपन्यासों के एक बड़े कोष में आवर्ती विषयगत पैटर्न की पहचान करने के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग कर सकता है, जिसे फिर निकट-पठन और ऐतिहासिक विश्लेषण के माध्यम से खोजा जा सकता है।

अधीनता को संबोधित करते हुएः जबकि व्याख्या मानविकी के लिए केंद्रीय है, यह व्यक्तिपरक के बारे में आलोचना का एक स्रोत हो सकता है। अनुभवजन्य तरीके अधिक वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य निष्कर्ष बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिससे मानविकी एक ऐसी दुनिया में अधिक विश्वसनीयता प्रदान करती है जो अक्सर डेटा और औसत दर्जे के परिणामों को प्राथमिकता देती है।

अंतःविषय सहयोगः अनुभवजन्य मोड़ अन्य क्षेत्रों, जैसे कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी और सामाजिक विज्ञान में मानविकी विद्वानों और विशेषज्ञों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इस अंतःविषय दृष्टिकोण से नवीन अनुसंधान प्रश्न और अधिक व्यापक उत्तर हो सकते हैं। 2.। जटिल सामाजिक मुद्दों से निपटना

प्रणालीगत असमानता को मापनाः अनुभवजन्य मानविकी के कुछ समर्थक विशेष रूप से नस्लवाद, लिंगवाद और वर्ग असमानता जैसे प्रणालीगत उत्पीड़न को मापने और उजागर करने के लिए डेटा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ₹विशेषाधिकार स्कोर₹ या शक्ति के समेकन पर नज़र रखने जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करके, इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और जवाबदेही की आवश्यकता के लिए अकाट्य प्रमाण प्रदान करना है।

सूचना नीति और अभ्यासः विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक तर्कों से परे जाकर, अनुभवजन्य मानविकी ठोस सबूत प्रदान कर सकती है जो नीति निर्माताओं, संस्थानों और कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने की अधिक संभावना है। डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि का उपयोग अधिक प्रभावी और न्यायसंगत कार्यक्रम और नीतियां बनाने के लिए किया जा सकता है। 3। अनुसंधान संभावनाओं का विस्तार

Unraveling Complexity: मानव अनुभव अविश्वसनीय रूप से जटिल है। अनुभवजन्य तरीके, विशेष रूप से बड़े डेटासेट (जैसे, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सोशल मीडिया डेटा) के कम्प्यूटेशनल विश्लेषण को शामिल करने वाले, विद्वानों को अंतर्निहित संरचनाओं और पैटर्न की पहचान करके इस जटिलता को ₹अनियंत्रित₹ करने में मदद कर सकते हैं जो अकेले पारंपरिक तरीकों के साथ देखना मुश्किल या असंभव होगा।

नए प्रश्नः नए अनुभवजन्य उपकरण और डेटा स्रोतों की उपलब्धता पूरी तरह से नए शोध प्रश्न खोलती है। उदाहरण के लिए, एक इतिहासकार एक ऐतिहासिक समुदाय के भीतर सामाजिक कनेक्शन और प्रभाव को मैप करने के लिए नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग कर सकता है, जबकि एक भाषाविद् लेखक के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए कम्प्यूटेशनल स्टाइलोमेट्री का उपयोग कर सकता है। तरीके और दृष्टिकोण अनुभवजन्य मानविकी अनुसंधान गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों को नियोजित कर सकता है, अक्सर संयोजन मेंः

गुणात्मक तरीकेः ये तरीके गैर-संख्यात्मक डेटा और घटनाओं के पीछे के संदर्भ को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरणों में शामिल हैंः

केस स्टडी

साक्षात्कार और फोकस समूह

पाठ विश्लेषण

नृवंशविज्ञान अवलोकन

मात्रात्मक तरीकेः ये तरीके संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरणों में शामिल हैंः

सर्वेक्षण और प्रश्नावली

प्रयोग

बड़े पाठ कॉर्पोरा का कम्प्यूटेशनल विश्लेषण (जैसे, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, पाठ खनन)

नेटवर्क विश्लेषण

डेटा विजुअलाइज़ेशन चुनौतियां और विचार जबकि अनुभवजन्य मानविकी की आवश्यकता तेजी से पहचानी जा रही है, चुनौतियां भी हैंः

पद्धतिगत प्रशिक्षणः कई मानविकी विद्वानों को अनुभवजन्य अनुसंधान विधियों और आंकड़ों में औपचारिक प्रशिक्षण की कमी है। इसके लिए शिक्षाशास्त्र में बदलाव और मानविकी कार्यक्रमों में पद्धतिगत कौशल पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

मानविकी प्रश्न की प्रकृतिः कुछ आलोचकों का तर्क है कि मानविकी में सबसे गहरा और सार्थक प्रश्न - अर्थ, सौंदर्य और व्यक्तिपरक अनुभव से संबंधित - अनुभवजन्य डेटा पर पूरी तरह से कब्जा या कम नहीं किया जा सकता है।

नैतिक चिंताएंः बड़े पैमाने पर डेटा का उपयोग, विशेष रूप से मानव व्यवहार के बारे में, गोपनीयता, सहमति और सूचना के दुरुपयोग की क्षमता के बारे में नैतिक प्रश्न उठाता है। अंत में, अनुभवजन्य मानविकी की ओर आंदोलन पारंपरिक छात्रवृत्ति की जगह लेने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समृद्ध करने के बारे में है। डेटा-संचालित तरीकों को गले लगाकर, मानविकी अधिक प्रासंगिक, कठोर और प्रभावशाली हो सकती है

अंत में, अनुभवजन्य मानविकी की ओर आंदोलन पारंपरिक छात्रवृत्ति की जगह लेने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समृद्ध करने के बारे में है। डेटा-संचालित तरीकों को गले लगाकर, मानविकी हमारे समय की सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों को संबोधित करने में अधिक प्रासंगिक, कठोर और प्रभावशाली बन सकती है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

एच-वन-बी वीज़ा विवाद और आत्मनिर्भर भारत का अवसर

(अमेरिकी एच-वन-बी वीज़ा विवाद : भारतीय प्रवासी के लिए संकट, भारत के लिए अवसर)

अमेरिका का नया एच-वन-बी वीज़ा शुल्क केवल आप्रवासन नीति का मुद्दा नहीं है बल्कि वैश्विक आर्थिक समीकरणों का संकेतक है। इससे भारतीय प्रवासी समुदाय में असुरक्षा तो बढ़ी है, लेकिन भारत के लिए यह रिवर्स ब्रेन ड्रेन का अवसर भी है। यदि लौटे हुए पेशेवरों के अनुभव, नेटवर्क और तकनीकी दक्षता को सही नीति समर्थन मिले तो भारत के स्टार्ट-अप, अनुसंधान और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिल सकती है। चुनौती को अवसर में बदलकर भारत न केवल अपने कौशल पूँजी का उपयोग करेगा बल्कि वैश्विक वैल्यू चेन में भी मज़बूती से उभरेगा

- डॉ सत्यवान सौरभ

हाल ही में अमेरिका ने अपनी बहुप्रतीक्षित एच-वन-बी वीज़ा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नए आवेदनों पर एक लाख अमेरिकी डॉलर की भारी फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय केवल आप्रवासन नीति का मामला नहीं है बल्कि बदलते वैश्विक आर्थिक समीकरणों और श्रम बाज़ार की गहरी हलचलों का प्रतीक है। भारतीय पेशेवर, जो अब तक एच-वन-बी वीज़ा धारकों का लगभग सत्तर प्रतिशत हिस्सा बनाते थे, इस कदम से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यही संकट भारत के लिए अवसर भी ला सकता है। यदि लौटती हुई प्रतिभाओं यानी रिवर्स ब्रेन ड्रेन का सही इस्तेमाल हो तो यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

एच-वन-बी वीज़ा लंबे समय से अमेरिकी तकनीकी कंपनियों की रीढ़ रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियों में बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवर कार्यरत हैं। किंतु अब अमेरिका में संरक्षणवादी रुझान और आर्थिक राष्ट्रवाद खुलकर सामने आ रहा है। विकसित देश अपने घरेलू श्रमिक वर्ग को संतुष्ट करने के दबाव में बाहरी प्रतिभाओं पर निर्भरता घटाने लगे हैं। यह एक विरोधाभासी स्थिति है क्योंकि अमेरिकी श्रम बाज़ार में उच्च तकनीकी क्षेत्रों में पर्याप्त घरेलू संसाधन नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव इसे बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिका आव्रजन को केवल श्रम गतिशीलता का विषय नहीं मानता बल्कि इसे व्यापारिक हथियार के रूप में भी प्रयोग कर रहा है। वीज़ा शुल्क में इस प्रकार की बढ़ोतरी से न केवल राजस्व अर्जित होगा बल्कि अन्य देशों पर राजनीतिक दबाव भी डाला जाएगा। इसी दौरान कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपनी आप्रवासन नीतियों को उदार बना रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का भूगोल बदल रहा है और अमेरिका का आकर्षण धीरे-धीरे कम हो सकता है।

इस नीति परिवर्तन का असर भारतीय प्रवासी समुदाय पर बहुआयामी है। एक ओर लाखों परिवारों में नौकरी की असुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता का माहौल बन गया है। बच्चों की पढ़ाई, सामाजिक जीवन और पारिवारिक स्थिरता पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत में इसका सकारात्मक पक्ष भी उभर रहा है। बड़ी संख्या में पेशेवर भारत लौटने के लिए प्रेरित होंगे। वे केवल पूँजी ही नहीं बल्कि वैश्विक अनुभव, नेटवर्क और तकनीकी दक्षता भी लेकर आएँगे। इस प्रकार भारत के स्टार्ट-अप और यूनिकॉर्न इकोसिस्टम को नई ऊर्जा मिल सकती है। विदेशों से लौटे पेशेवरों के पास निवेशकों का दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार का अनुभव होगा, जिससे भारत का उद्यमिता वातावरण और मजबूत हो सकता है।

एक और बड़ा अवसर यह है कि लौटे हुए विशेषज्ञ भारत के अनुसंधान और विकास क्षेत्र में अहम योगदान देंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। यदि लौटे हुए वैज्ञानिक और इंजीनियर भारतीय संस्थानों से जुड़ें तो देश में नवाचार की गति तेज़ हो सकती है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को वास्तविक बल मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलें उन प्रतिभाशाली पेशेवरों की मदद से मज़बूत होंगी जो विदेशों में आधुनिक तकनीकी अनुभव लेकर आएंगे।

भारत के लिए यह समय केवल इंतजार करने का नहीं है, बल्कि ठोस नीतिगत कदम उठाने का है। सरकार को लौटती प्रतिभाओं का स्वागत करने के लिए विशेष योजनाएँ बनानी होंगी। उदाहरण के लिए रिटर्निंग टैलेंट स्कीम के तहत विदेशों से लौटने वाले पेशेवरों को कर में छूट, निवेश प्रोत्साहन और विशेष स्टार्ट-अप पैकेज दिए जा सकते हैं। विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग के लिए उच्चस्तरीय शोध प्रयोगशालाएँ और नवाचार केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। निजी क्षेत्र को अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने के लिए कर रियायत और प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके साथ ही वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स को प्रवासी पेशेवरों के अनुभव से जोड़कर वित्तीय इकोसिस्टम को मज़बूत करना आवश्यक होगा।

लौटे हुए प्रवासियों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक पुनर्वास योजनाएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि उन्हें भारत में बसने के दौरान कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी तो उनकी प्रतिभा का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं में उन्हें आसानी उपलब्ध करानी होगी ताकि वे बिना किसी झंझट के समाज और अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकें।

इस प्रकार एच-वन-बी वीज़ा विवाद भारत के सामने दोहरी चुनौती पेश करता है। एक ओर लाखों प्रवासी भारतीयों की आजीविका और भविष्य की चिंता है, तो दूसरी ओर यही संकट भारत के लिए सुनहरा अवसर भी है। यदि भारत इस अवसर का लाभ उठाकर रिवर्स ब्रेन ड्रेन को अपनी ताकत बना लेता है तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। संकट हमें यह याद दिलाता है कि आत्मनिर्भरता केवल नारे से नहीं बल्कि दूरदर्शी नीतियों और वैश्विक अवसरों को साधने की क्षमता से संभव है।

पंडित दीनदयाल: भारतीयता के संवाहक, विचारों के युग-पुरुष

भारत की आत्मा को यदि किसी विचार ने गहराई से स्पर्श किया है, तो वह है "एकात्म मानववाद", और इसके प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनकी जयंती, 25 सितंबर, केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक विचार की पुनर्जनन की प्रेरणा है—एक ऐसे भारत का संकल्प, जहाँ समाज का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा में शामिल हो। दीनदयाल जी का जीवन सादगी का प्रतीक था, उनका चिंतन ऊँचा और दृष्टिकोण इतना विशाल कि वह आज भी हमें दिशा देता है। वे न केवल एक राजनेता या दार्शनिक थे, बल्कि भारतीय संस्कृति के संवाहक, सामाजिक अभियंता और एक ऐसे युग-पुरुष थे, जिनके विचारों ने भारत को अपनी जड़ों से जोड़कर भविष्य का रास्ता दिखाया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नगला चंद्रभान गाँव में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर थे, और माता रामप्यारी धर्मपरायण थीं। बचपन में ही माता-पिता का साया खो देने के बावजूद, उनके नाना चुन्नीलाल शुक्ल ने उन्हें पाला। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत थी—हर संकट में अवसर ढूँढना और हर कठिनाई में संतुलन बनाए रखना। यही गुण बाद में उनके वैचारिक और सामाजिक जीवन का आधार बना।

उनकी शिक्षा मथुरा, सिकंदराबाद, इलाहाबाद और कानपुर में हुई। गणित और संस्कृत में उनकी गहरी रुचि थी, और वे हमेशा अव्वल रहे। लेकिन उनकी असली शिक्षा समाज के बीच हुई। गाँवों में घूमकर, किसानों-मजदूरों से मिलकर, उन्होंने भारत की आत्मा को समझा। उनका मानना था कि भारत की प्रगति की कुंजी उसकी मिट्टी, उसके गाँवों और उसके लोगों में छिपी है। इस सोच ने उन्हें 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का पूर्णकालिक प्रचारक बनने के लिए प्रेरित किया, जहाँ उन्होंने संगठन, अनुशासन और सेवा के मूल्यों को आत्मसात किया।

आरएसएस में उनकी संगठन क्षमता ने उन्हें उत्तर प्रदेश में एक मजबूत आधार दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना में रहा, जिसे उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर स्थापित किया। जनसंघ के महासचिव और बाद में अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने संगठन को वैचारिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर मजबूत किया। उनके लिए राजनीति सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज के कल्याण का साधन थी। वे कहा करते थे, "हम सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए राजनीति करते हैं।" यह दृष्टिकोण आज भी भारतीय राजनीति में प्रासंगिक है, जब नेतृत्व से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के हित को सर्वोपरि रखे।

दीनदयाल जी का सबसे क्रांतिकारी योगदान "एकात्म मानववाद" का दर्शन है। उस दौर में जब विश्व पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच बँटा था, दीनदयाल जी ने भारत के लिए एक तीसरा रास्ता सुझाया। पूँजीवाद व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ावा देता है, और साम्यवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलता है। इसके विपरीत, एकात्म मानववाद मनुष्य को एक समग्र इकाई मानता है—शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन। उनका कहना था कि विकास केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक होना चाहिए। यह दर्शन भारत की सनातन परंपराओं से प्रेरित था, जो व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य की बात करता है।

इस दर्शन का मूल आधार था "अंत्योदय"—समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का उत्थान। दीनदयाल जी का मानना था कि किसी भी नीति की सफलता का पैमाना यह है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक कितनी पहुँचती है। यह विचार आज भारत की नीतियों में स्पष्ट दिखता है—चाहे वह गरीब कल्याण योजनाएँ हों या समावेशी विकास के प्रयास। उनकी यह सोच सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखती है, जो आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है।

दीनदयाल जी की पर्यावरण के प्रति चेतना भी उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है। वे मानते थे कि प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता सहजीवन का होना चाहिए। उनकी "धर्मक्षेत्रे-कुरुक्षेत्रे" की अवधारणा में धर्म को केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि प्रकृति, समाज और व्यक्ति के बीच संतुलन का विज्ञान बताया। आज जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट वैश्विक चुनौती हैं, उनकी यह सोच सतत विकास की दिशा में एक मार्गदर्शक है।

पत्रकारिता में भी उनका योगदान उल्लेखनीय था। उन्होंने 'राष्ट्रधर्म', 'पांचजन्य' और 'स्वदेश' जैसे पत्रों का संपादन किया, जिनके माध्यम से उन्होंने भारतीयता, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचारों को जन-जन तक पहुँचाया। उनकी लेखनी में गहराई थी, लेकिन वह इतनी सरल थी कि सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सकता था। वे मानते थे कि विचारों का प्रसार ही समाज को जागृत करता है, और उनकी लेखनी इस दिशा में एक शक्तिशाली हथियार थी।

उनका व्यक्तिगत जीवन सादगी और अनुशासन का अनुपम उदाहरण था। साधारण वस्त्र, सादा भोजन और न्यूनतम आवश्यकताएँ—उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्चा नेता समाज के लिए जीता है, न कि व्यक्तिगत सुख के लिए। उनके सहयोगी बताते हैं कि वे रात-रात भर संगठन के लिए काम करते, लेकिन कभी थकान की शिकायत नहीं करते। उनकी यह निस्वार्थ भावना आज के नेताओं के लिए एक प्रेरणा है।

दुर्भाग्यवश, 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। यह एक अपूरणीय क्षति थी, लेकिन उनके विचारों ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचार भारतीय राजनीति और समाज में गूँजते रहे। आज उनकी जयंती पर हम केवल उनकी स्मृति को नमन नहीं करते, बल्कि उनके दर्शन को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं।

आज के दौर में, जब वैश्वीकरण हमें अपनी जड़ों से काटने का प्रयास करता है, दीनदयाल जी का चिंतन हमें भारतीयता की ओर लौटने का आह्वान करता है। जब विकास की परिभाषा केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित हो जाती है, तब उनका एकात्म मानववाद हमें याद दिलाता है कि विकास बहुआयामी होना चाहिए—नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। उनकी जयंती हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या हमने उनके विचारों को अपने जीवन में उतारा है? क्या हम उस भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान और समृद्धि के साथ जी सके?

दीनदयाल जी का जीवन हमें सिखाता है कि साधारण परिस्थितियों में जन्मा व्यक्ति भी, यदि अपने विचारों में दृढ़ और कर्म में निष्कलुष हो, तो वह राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। उनकी जयंती केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य का संकल्प है—एक ऐसे भारत का निर्माण, जहाँ अंत्योदय से समग्र विकास तक की यात्रा पूरी हो। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम उनकी शिक्षाओं को अपनाएँ, भारतीय संस्कृति की आत्मा को जीवित रखें, और राजनीति को सेवा का माध्यम बनाएँ। दीनदयाल जी का जीवन और विचार आज भी हमें एक उज्ज्वल, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाते हैं।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी

अंग्रेजी आवश्यक है

विजय गर्ग

भाषा का महत्व एक समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच संचार के प्राथमिक साधन के रूप में इसकी भूमिका में है। विज्ञान और अनुसंधान की उन्नति और विकास के साथ, अंग्रेजी विज्ञान और संस्कृति की भाषा के रूप में उभरी है। यह उद्भव अनुसंधान, वैज्ञानिक, ज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पश्चिमी समाज की प्रगति का परिणाम है। इस प्रकार, इस प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए, अंग्रेजी में महारत हासिल करना आवश्यक है। यह लेख अंग्रेजी सीखने के दस कारणों को रेखांकित करता है।

वैश्विक संचार अंग्रेजी सभी विश्व भाषाओं के बीच एक भाषा फ्रैंका के रूप में कार्य करती है, जिससे हम विश्व स्तर पर संवाद कर सकते हैं और भाषा बाधाओं को पार कर सकते हैं।

रोजगार के अवसर वैश्विक खुलेपन ने नौकरी की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है, जिसमें अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में संचार का एक मौलिक और प्रमुख साधन है, जहां विभिन्न राष्ट्रीयताओं के कर्मचारी इकट्ठा होते हैं। इस प्रकार, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसरों के लिए एक विस्तृत क्षितिज खोलता है। उच्च शिक्षा कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री सहित उच्च शिक्षा को पूरा करने के लिए अंग्रेजी में प्रवीणता एक मौलिक आवश्यकता है। संस्कृति और मनोरंजन मनोरंजन में प्रगति ने इस क्षेत्र के लिए अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा बना दिया है, जिससे फिल्मों और पुस्तकों के माध्यम से वैश्विक संस्कृति की गहरी समझ का दरवाजा खुल गया है।

प्रौद्योगिकी और विज्ञान अंग्रेजी की महारत प्रौद्योगिकी और विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में नवीनतम विकास के साथ रखने में सक्षम बनाती है, क्योंकि यह वह भाषा है जिसमें नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान लिखा गया है और वर्तमान में प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा है।

इंटरनेट संचार अंग्रेजी प्राथमिक इंटरनेट भाषा है, जिससे वेब ब्राउज़ करने और नवीनतम वैश्विक विकास और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी अच्छी समझ आवश्यक है।

सोशल नेटवर्किंग और अंतर्राष्ट्रीय संचार संपर्कों के अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लक्ष्य रखने वालों के लिए, अंग्रेजी दुनिया भर के दोस्तों और सहकर्मियों के साथ संचार को बढ़ाती है।

यात्रा और वैश्विक व्यापार अंग्रेजी दुनिया भर के व्यापारियों के बीच एक आम भाषा के रूप में वैश्विक बाजारों में चिकनी यात्रा और वाणिज्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार वातावरण और एड्स में बातचीत की सुविधा प्रदान करती है। सांस्कृतिक समझ जो लोग विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं की गहराई की यात्रा करना और उनका पता लगाना पसंद करते हैं, उनके लिए अंग्रेजी विभिन्न रीति-रिवाजों और परंपराओं को समझने में मदद करती है, सांस्कृतिक बातचीत को बढ़ाती है। व्यक्तिगत विकास जो अंग्रेजी को अलग करता है वह सामाजिक विकास के परिणामस्वरूप अभिनव शब्दों के लिए उसका समकालीन स्वभाव और खुलापन है। जितना गहरा आप इसे सीखने में तल्लीन होते हैं, उतना ही आपका कौशल विकसित होता है।

अंग्रेजी सीखना भाषा कौशल में सुधार तक सीमित नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक और पेशेवर जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के लिए विस्तारित है। वैश्विक संचार और संस्कृति, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के अवसरों से, अंग्रेजी हमारे क्षितिज को व्यापक बनाने और हमारे मानव अनुभव को समृद्ध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंग्रेजी केवल एक संचार उपकरण नहीं है, बल्कि एक पुल है जो हमें दुनिया से जोड़ता है, ज्ञान के दरवाजे खोलता है, और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सहायता करने वाले कौशल प्रदान करता है। एक जुड़ी और विकसित दुनिया में, अंग्रेजी सीखना एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है, जो प्रगति के साथ तालमेल रखने और वैश्विक समुदाय में प्रभावी रूप से एकीकृत करने के लिए आवश्यक है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर

कक्षा से कैरियर

विजय गर्ग

कक्षा से करियर में संक्रमण अक्सर छात्रों और हाल के स्नातकों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अकादमिक ज्ञान हमेशा पेशेवर दुनिया में आवश्यक कौशल का सीधे अनुवाद नहीं करता है। अंतर मौजूद है क्योंकि कई शैक्षणिक कार्यक्रम सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि नियोक्ता व्यावहारिक कौशल और वास्तविक दुनिया के अनुभव को प्राथमिकता देते हैं। इस अंतर को पाटने के लिए, व्यक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों दोनों को सक्रिय कदम उठाने चाहिए। छात्रों और नौकरी चाहने वालों के लिए रणनीतियाँ

व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंः इंटर्नशिप, सह-ऑप कार्यक्रम, और आपके क्षेत्र में अंशकालिक नौकरियां अमूल्य हैं। वे पेशेवर दुनिया का स्वाद प्रदान करते हैं और आपको वास्तविक दुनिया के संदर्भ में जो कुछ भी सीखा है उसे लागू करने की अनुमति देते हैं।

सॉफ्ट स्किल्स विकसित करेंः ये गैर-तकनीकी कौशल हैं जो किसी भी कार्यस्थल में सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। नियोक्ता अत्यधिक मूल्य संचार, टीम वर्क, समस्या को सुलझाने, महत्वपूर्ण सोच और अनुकूलनशीलता। इन क्षमताओं को सुधारने के लिए समूह परियोजनाओं, स्वयंसेवक या छात्र क्लबों में शामिल हों।

एक पेशेवर नेटवर्क बनाएंः कैरियर मेलों, उद्योग सम्मेलनों और नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लें। लिंक्डइन जैसे प्लेटफार्मों पर पेशेवरों के साथ जुड़ें। आपका नेटवर्क आपके चुने हुए क्षेत्र में मेंटरशिप, जॉब लीड और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएंः अपने काम का एक पोर्टफोलियो, चाहे वह आपकी कोडिंग परियोजनाओं, डिजाइन के काम का संग्रह, या अनुसंधान पत्रों का एक पोर्टफोलियो प्रदर्शित करने वाली वेबसाइट हो, आपके कौशल और क्षमताओं का ठोस प्रमाण प्रदान करती है।

आजीवन सीखने को गले लगाओः नौकरी बाजार लगातार विकसित हो रहा है। लगातार नए कौशल सीखने और अपने उद्योग में बदलाव के अनुकूल होने के लिए तैयार रहें। इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेना, प्रमाणपत्र अर्जित करना या आगे की शिक्षा प्राप्त करना शामिल हो सकता है। शैक्षिक संस्थानों की भूमिका

रियल-वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को एकीकृत करेंः करिकुलम में प्रोजेक्ट-आधारित लर्निंग और केस स्टडीज शामिल होने चाहिए जो पेशेवर दुनिया में आने वाली चुनौतियों की नकल करते हैं। यह छात्रों को केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, करने से सीखने में मदद करता है।

फोस्टर इंडस्ट्री पार्टनरशिपः व्यवसायों और संगठनों के साथ सहयोग छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर, पेशेवरों से अतिथि व्याख्यान और एक पाठ्यक्रम प्रदान कर सकता है जो वर्तमान उद्योग की जरूरतों के साथ गठबंधन किया गया है।

कैरियर सेवाओं को मजबूत करेंः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से शुरू कार्यशालाओं, मॉक इंटरव्यू और व्यक्तिगत कैरियर परामर्श सहित व्यापक कैरियर समर्थन की पेशकश करनी चाहिए। उन्हें छात्रों को नियोक्ताओं और पूर्व छात्रों के साथ सक्रिय रूप से जोड़ना चाहिए।

सॉफ्ट स्किल्स पर जोर देंः शिक्षकों को जानबूझकर अपने शिक्षण विधियों में नरम कौशल के विकास को शामिल करना चाहिए, वर्ग चर्चा, समूह प्रस्तुतियों और सहयोगी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर

झारखंड के रांची , जमशेदपुर , धानबाद में चलेगी अब मेट्रो रेल , केंद्र सरकार ने राज्य से मांगा प्लान ब्यौरा

यहां रेल गाड़ी दौड़ने के सवा सौ वर्ष के बाद अब जमशेदपुर देखेगा अब मेट्रो रेल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

जमशेदपुर ,सन 1883 में बंगाल से जमशेदपुर होते नागपुर तक तत्कालीन रेललाइन बिछाने हेतु हावड़ा नागपुर रेल कंपनी की मालिक उस अंग्रेज सरकार ने धालभूम राजा , सरायकेला रजा एवं खरसावां राजा से जमीन मांगी की थी जहां आज हाबडा मुबंई रेल 1968 किलोमीटर का लम्बा मार्ग इसी जमशेदपुर से होकर गुजरता है । यहां पब्लिक , माल ढुलाई हेतु रेल गाड़ी आवाजाही 1900 ई में आरंभ हुई । तब टाटा नगर स्टेशन का नाम कालीमाटी स्टेशन हुआ करता था ,जो उस कालीमाटी गांव के नाम पर नामित था ।बढ़ती आबादी मद्देनजर गत दिनों झारखंड राज्य सरकार ने मेट्रो रेल शहरों में चलाने की मांग केंद्र से की थी । राजधानी रांची समेत दो अन्य औधौगिक शहरों जमशेदपुर, धनबाद को अब मेट्रो रेल कि चलने सवा सौ वर्ष के बाद केंद्र सरकार सौगात के तौर आरंभ करने जा रही है ,जिसके लिए काम अब श्रीगणेश होगा ।

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मांग पर अब केंद्र सरकार ने प्रदेश के 3 शहरों के लिए मेट्रो ट्रेन का प्लान मांगा है. झारखंड के 3 प्रमुख शहरों को लेकर केंद्र सरकार ने सकारात्मक पहल की है. राज्य सरकार रांची, जमशेदपुर और धनबाद को राष्ट्रीय पैमाने पर विकसित शहर के तौर पर लाना चाहती हैं.

इसे लेकर नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि झारखंड में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अभाव है, हमारे पास सार्वजनिक परिवहन प्रणाली देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिल कर उनसे आग्रह किया था कि कम से कम राजधानी रांची को मेट्रो रेल मिलना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री ने कहा जिस आबादी को कैटर करने का क्राइटेरिया है उसमें झारखंड के शहर नहीं आते हैं. हमने मांग किया था कि झारखंड की आबादी ही कम है, . इसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वस्त किया था कि प्री फिजीबिलिटी रिपोर्ट में अगर झारखंड के शहर अप टू मार्क आते हैं तो केंद्र सरकार से मदद मिलेगी. हाल के दिनों में भारत सरकार से प्री फिजीबिलिटी के लिए झारखंड के शहरों के नाम मांगे गए थे जो राज्य सरकार भेज रही है.

उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं इस छोटे से हिली स्टेट जहां बहुसंख्यक एसटी आबादी का निवास है, राज्य सरकार की अपेक्षाओं के अनुरुप केंद्र सरकार अपने नियमों को शिथिल करते हुए जिस तरीके से उड़ीसा में भुवनेश्वर के लिए किया है. उसी तरह से रांची में मेट्रो निर्माण की अनुमति प्रदान करें. राज्य सरकार बहुत आशान्वित है कि केंद्र की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद बड़ी तीव्र गति से इसका निर्माण कर रांची, जमशेदपुर और धनबाद को राष्ट्रीय पैमाने पर विकसित शहर के तौर पर लाना चाहते हैं।

शक्ति और साहस का पर्व है नवरात्रि

रमेश सर्राफ धमोरा

नवरात्रि का मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा और आराधना के लिए समर्पित है जिन्हें शक्ति, साहस, और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 'नौ रातें', और इस दौरान भक्त देवी दुर्गा की विशेष पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, और भक्ति में लीन रहते हैं। नवरात्रि का त्योहार एक बार वसंत ऋतु के दौरान चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु के दौरान शरद नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शरद नवरात्रि अश्विन के महीने के दौरान मनाई जाती है जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आती है। वहीं चैत्र नवरात्रि हिन्दू कैलेंडर के चैत्र महीने के दौरान मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि आमतौर पर मार्च या अप्रैल महीने में मनाई जाती है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति- देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दसवां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है।

वसन्त की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत, जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते है। त्योहार की तिथियां चन्द्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से है। नवरात्रि के पहले तीन दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उनकी ऊर्जा और शक्ति की की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है।

नवरात्रि से हमें अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई के जीत की सीख मिलती हैं। यह हमें बताती है की इंसान अपने अंदर की मूलभूत अच्छाइयों से नकारात्मकता पर विजय प्राप्ती और स्वयं के अलौकिक स्वरूप से साक्षात्कार कैसे कर सकता है। भारतीय जन-जीवन में धर्म की महत्ता अपरम्पार है। यह भारत की गंगा-जमुना तहजीब का ही नतीजा है कि सब धर्मों को मानने वाले लोग अपने-अपने धर्म को मानते हुए इस देश में भाईचारे की भावना के साथ सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं। यही कारण है की पूरे विश्व में भारत की धर्म व संस्कृति सर्वोतम मानी गयी है। विभिन्न धर्मों के साथ जुड़े कई पर्व भी है जिसे भारत के कोने - कोने में श्रध्दा, भक्ति और धूमधाम से मनाया जाता है। उन्ही में से एक है नवरात्रि।

नवरात्रि पर्व के नौ दिनों के दौरान आदिशक्ति जगदम्बा के नौ विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। ये नौ दिन वर्ष के सर्वाधिक पवित्र दिवस माने गए हैं। इन नो दिनों का भारतीय धर्म एवं दर्शन में ऐतिहासिक महत्व है और इन्हीं दिनों में बहुत सी दिव्य घटनाओं के घटने की जानकारी हिन्दू पौराणिक ग्रन्थों में मिलती है। माता के इन नौ रूपों को नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है जो इस प्रकार हैं - शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघन्टा, कूष्माण्डा, स्कन्द माता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी और सिध्दिदात्री।

नवरात्रि वर्ष में चार बार आता है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पौष प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ रातों में तीन देवियों महालक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के नौ स्वरुपों की पूजा होती है जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटानेवाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि साल में दो बार मनाया जाता है। हिंदी महीनो के मुताबिक पहला नवरात्रि चैत्र महीने में मनाया जाता है और दूसरी बार अश्विन महीने में मनाया जाता है। नवरात्रि नौ दिनों तक निरंतर चलता है जिसमे देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की लोग भक्ति और निष्ठा के साथ पूजा करते है। भारत में नवरात्रि अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरीको और विधियों के संग मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं नौ दिनों में मां दुर्गा धरती पर आती है। उनके आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गा उत्सव के तौर पर देशभर में धूमधाम से मनाया जाता हैं।

नवरात्रि के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है। दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है। तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गयी है, उसकि पूजा की जाती है। नवरात्रि के चैथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी- समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। आठवे दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। नौवा दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उन नौ जवान लड़कियों की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इन नौ लड़कियों को देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को उपहार के रूप में नए कपड़े, वस्तुयें, फल प्रदान किए जाते हैं।

झारखंड में पुनः मुठभेड़, दो कमांडर समेत तीन उग्रवादी ढेर

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , गुमला जिले में बुधवार तड़के झारखंड की जेजेएमपी और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने तीन उग्रवादियों को ढेर कर दिया

झारखंड के जंगलों में झारखंड जनमुक्ति परिषद यानी जेजेएमपी और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने तीन उग्रवादियों को ढेर कर दिया है. दो सब जोनल कमांडरों की भी मौत हुई है. मृतकों की पहचान हो गई है. एक का नाम- लालू लोहरा, दूसरे का नाम- छोटू उरांव और तीसरे का नाम- सुजीत उरांव है.

लालू जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर था. पुलिस ने उसके पास से एके-47 बरामद की है. पांच

लाख का इनाम भी उसके ऊपर घोषित था. छोटू उराव भी सब जोनल कमांडर था. वह भी पांच लाख रुपये का इनामी था. तीसरा जेजेपीसी का कैडर था. तीनों लंबे वक्त से तीनों क्षेत्र में एक्टिव थे. तीन ने कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है.

गुमला जिले के एसपी हासिल बिन जमां के नेतृत्व में पुलिस बल और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया. पूरे अभियान की कमान खुद एसपी ने ही संभाली. पुलिस ने जंगलों को चारों ओर से घेर लिया और सील कर दिया. गांव के रास्ते का आवागमन भी पूर्ण रूप से रोक दिया गया. आवागमन पूरी तरह गांव के रास्तों पर प्रतिबंधित कर दिया गया. ग्रामीणों से अपील की गई है कि घर में ही रहे और सतर्क रहें.

मुठभेड़ की खबर से आसपास के गावों में दहशत फैल गई है. इस इलाके में लंबे वक्त से रंगदारी, हथियारबंदी सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था .

उल्लेखनीय है कि गुमला जिले का ये क्षेत्र पहले भाकपा का गढ़ माना जाता था. माओवादियों के कमजोर होने के बाद जेजेएमपी ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है. कई बार दोनों सगंठनों के बीच, वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिलता था।

वर्तमान में भारत का राजनैतिक परिदृश्य

डॉ. मुश्ताक अहमद

हरदा। वर्तमान में भारत का राजनीतिक परिदृश्य काफी जटिल और गतिशील स्थिति में है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव और संघर्ष देखे जा रहे हैं। अब राजनीति केवल दो प्रमुख दलों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि क्षेत्रीय और समाजवादी दलों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास भूमिका निभानी शुरू कर दी है। यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र की बहुलता और विविधता को दर्शाता है।भाजपा ने सत्ता में मजबूती से बने रहने के बावजूद कई चुनौतियों का सामना किया है। विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस, संगठनात्मक बदलावों और नए रणनीतियों के साथ पुनः उभरने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों और लोकसभा उपचुनावों में इस प्रतिस्पर्धा की झलक साफ दिखाई देती है। साथ ही, क्षेत्रीय दल जैसे कि आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और अन्य भी स्थानीय मुद्दों के आधार पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं।राजनीतिक संवाद और विरोधाभास संसद और सड़कों दोनों पर तीव्र हो गए हैं। अक्सर संसद सत्रों में भारी हंगामा और विरोध प्रदर्शन होते देखे जा रहे हैं, जिससे विधायी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। सामाजिक, जातीय और धार्मिक मुद्दे राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में बने हुए हैं। जाति आधारित जनगणना, नागरिक संहिता जैसे संवेदनशील विषय राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों को बढ़ावा दे रहे हैं।2025 में दिल्ली, बिहार और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे बड़े राजनीतिक नेतृत्यों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण होंगे। ये चुनाव केवल राज्यों की सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली बदलाव का संकेत भी देने वाले हैं।सरकार के जन-कल्याण और विकास योजनाओं के बावजूद किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। इसके अलावा, ₹एक राष्ट्र, एक चुनाव₹ की पहल भी राजनीतिक बहस में महत्वपूर्ण जगह रखती है।सरकारी नीतियों के एकांगीकरण, सामाजिक संगठनों का दबाव और मीडिया के स्वर विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाते हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र जीवंत और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।इस प्रकार, वर्तमान में भारत का राजनीतिक परिदृश्य बहु-मुखी, प्रतिस्पर्धी और गतिशील है, जिसमें लोकतंत्र की विविधता और विभिन्नता के साथ राजनीतिक नेतृत्व की चुनौतियाँ भी स्पष्ट देखी जा सकती हैं।।

व्यंग्य : ये तो मेरे सरकार , खिलाड़ियों का नया अंदाज है ।

क्रिकेट जगत के बड़े-बड़े भविष्यवक्ता , पंडित भी दावे से साथ नहीं कर सकते हैं कि , क्रिकेट कब रंग बदलते , क्रिकेट का ऊंट किस करवट बैठेगा यह तय नहीं है । क्रिकेट के मैदान में ऐसे ही रंग बदलते माहौल में किसी के ₹ हाथ ₹ से कोई ऐसी घटना घट जाती है जो इतिहास में दर्ज हो जाती है । " हाथ न मिलाने" का ऐसा ही वाकिया घट गया । इस अवसर पर हर कोई लिखना चाहता है ।

खेल भावना तो यही कहती है कि , मैच जीतने के बाद सभी खिलाड़ी एक दूसरे से ₹ हाथ ₹ मिलाते हैं और ₹ पंजा ₹ लड़ाने लग जाते तो कोई खिलाड़ी ₹ पहलवान ₹ की तरह गुलाटी मारत है फिर वह आदर , सम्मान के साथ ख़ुशी ख़ुशी विदा होते हैं कुछ परिस्थितियों एवं घटनाओं से सबक लेते हुएं । देश के वातावरण में बदलाव आ चुका है और देश बदल रहा है जिसके कारण हम सभी को सब कुछ साफ़ साफ़ नजर आने लगा है । कौन अपने दामन में ₹ पाक ₹ और कौन अपने दामन में ₹ नापाक ₹ है सब अच्छी तरह जानते हैं । वैसे भी कोरोना काल की राजनीति में हमे समझ आ गया था कि किससे ₹ हाथ ₹ मिलाना है और किससे ₹ हाथ ₹ नहीं मिलाना है समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं । सवाल अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो , वह खेल के (राजनीति के) मैदान में अपने खेल का प्रदर्शन करके उन जवाबदेही विचारों का वास्तविक ₹ अर्थ ₹ धरातल पर उतारना ही मेरे ₹ सरकार ₹ खिलाड़ियों का नया ₹ अंदाज ₹ है । किसी शायर ने भी क्या खूब कहा

₹ मुझे दिखावे की मुहब्बत पसंद नहीं है गर तुम दिल में कोई साजिश रचते हो ₹

दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकता चाहे वह राजनीति में हो या किसी खेल मैदान में ही क्यों न हो ।

एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान आगा से हाथ नहीं मिलाया । इस विषय की चर्चा हवा में आगा

₹ आग ₹ की तरह फेल गई । यह तो ₹ नौ हेंड शेक पॉलिसी ₹ की नीति है जो कूटनीति के रूप में दिखाई दे रही है । जिसे देखकर ऐसा लगता है कि राजनीति के प्याले में चाय उबल गई हो । खेल के मैदान में मेरे सरकार ने राजनीति की ऐसी कूटनीति चलाई थी सामने वाला मैदान में देखता ही रह और खेल में रन के लिए कूटनीति ने ऐसी दौड़ गई कि , आगा हाथ मिलाते मिलाते रह गया आश्चर्य जनक बात यह है कि , इस देश में खिलाडी की , गेंदबाजी की , बल्लेबाजी की , किसी खिलाडी के प्रदर्शन की चर्चा उतनी नहीं हो रही है जितनी उन हाथों की हो रही है । अरे भाई यही तो कूटनीति है जिसने हाथों-हाथ , हाथ का कमाल हो गया जो जीत के लिए खेल है थे और खेल ही खेल में खिलाड़ियों ने ऐसा खेल दिखाया की पाक कप्तान आगा बुरी तरह नापाक होते हुए दिखाई दिये जिसके चलते हाथ नहीं मिला पाया । इस का कारण आईने की तरह साफ दिखाई दे रहा है । इशारों को समझो तो राज को राज ही रहने दो ।

असली बात तो यह है कि₹ नो हैंडसेट पॉलिसी हैं ₹ जिसने चमत्कार दिखाया तो सामने वाला दूर से खड़ा होकर हाथ मलता ही रह गया और खिचयनी बिल्ली खंबा नोचे की तरह दिखाई देने लगा।

प्रकाश हेमावत

बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ का मंत्र है: अधूरी नहीं हूँ

डा. नीरज भारद्वाज

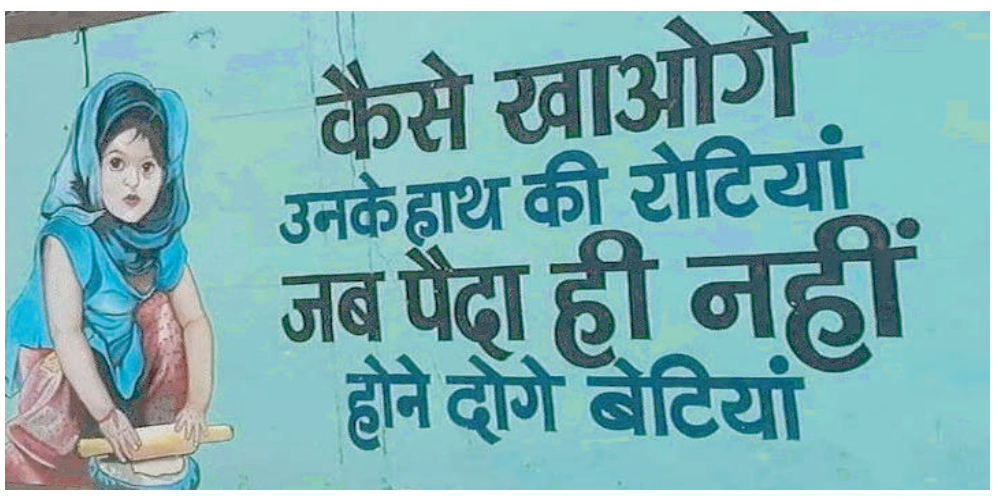

अधूरी नहीं हूँ कहानी संग्रह डा. अंजु वेद का पहला कहानी संग्रह है। यह कहानी संग्रह कई मायनों में अलग है। संग्रह को पढ़ते हुए न जाने कितने ही साहित्यकार और रचनाएँ मन मस्तिष्क को छू गए। इतना ही नहीं कहानी संग्रह ने समाज को नई रोशनी और नए विचार देने का बहुत बड़ा कार्य किया है। यह सृष्टि नर और नारी के योग से ही आगे बढ़ी है, लेखिका ने तो अपने नाम में ही मान लिया है कि वह अधूरी नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसका सहचर और प्रिय है।

संग्रह के समर्पण में लेखिका लिखती हैं कि- कहानी पढ़ने- सुनने वाले उन सभी को जो कहानी को केवल कल्पना अथवा मनोरंजन नहीं मानते अपितु जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। इस बात से स्पष्ट है कि कहानी कहीं और नहीं है वह हमारे और आपके आसपास ही विचरण करती रहती है। बस उसे देखने,समझने व लिखने का हौसला आपके पास होना चाहिए।

कहानी संग्रह में पारिवारिक संघर्ष को लेखिका ने खूब जमकर लिखा है। हर एक कहानी में पारिवारिक संघर्ष और वह भी लड़की अर्थात्नारी को ही करना पड़ता है, इसे दिखाने का पूरा प्रयास किया है।

कितने ही मिथकों को तोड़ता यह कहानी संग्रह बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ को स्पष्ट करता नजर आता है। हर एक कहानी में प्रमुख पात्र नारी ही है। वह संघर्ष से खड़ी होती है, पढ़ती लिखती है, घर का झाड़ू चौका करती है, बच्चे पालती है, कामकाज करती आधुनिक समाज में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती नजर आती है।

कुनिया कहानी में कुनिया विद्यालय जाती है, पढ़ने में धीरे-धीरे रुचि बनती है। लेकिन जल्द ही काल का ग्रास बन जाती है। अध्यापिका कुनिया के घर तक पहुँचती है परंतु तब तक कुनिया इस दुनिया से जा चुकी होती है। कहानी में अध्यापिका को अर्थात नारी को शिक्षित व समाज हितेषी और ममता का प्रतीक दिखाया गया है।

अधूरी नहीं हूँ नामक कहानी में यशवंती को पढ़ा-लिखा दिखाया गया है। कहानी के आरंभ में ही कहानीकार लिखती हैं कि- यशवंती तीनों भाइयों से अधिक पढ़ी थी। राघवदास बेटी की समझदारी पर अक्सर बेटों को डाँटा करता- कुछ सीखो इससे....उसी घर में तुम रहते हो और उसी में यह....ये घर को सँवारती है और तुम...। यशवंती पुनीत के साथ प्रणय सूत्र में बंध जाती है। लेकिन पुनीत पिता नहीं बन सकता। यशवंती यहाँ हार नहीं मानती है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर वह पति के साथ रहना चाहती है। लेकिन पति को यह सभी कुछ ठीक नहीं लगता। यशवंती हिम्मत से काम लेती है। यशवंती ने माँ-बाबूजी की बागवानी को अपना उद्यम बनाया। मसाले उगाए और उनका व्यापार आरंभ किया। नए काम में, आत्मनिर्भरता की धुन में जब कभी वह निराश होती तो बाबूजी की सिखाई बातें उसका मार्गदर्शन करतीं। इतना ही नहीं यशवंती एक बच्ची को गोद लेकर समाज के सामने एक नया उदाहरण भी रखती है। माँ-बाप बनना या न बनना नियति के हाथ है। बदलती सोच ने जहाँ चाह, वहाँ राह को दिखाया है।

कल्पना कहानी में नारी के त्याग, समर्पण, प्रेम को दिखाया है। साथ ही पढ़ी-लिखी लड़की कल्पना ने किस प्रकार अपने परिवार को संभाला, इस बात को बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया है।

क्या अपराध था नामक कहानी रेवती की मृत्यु के साथ शुरू होती है। रेवती के पति को सजा मिलती है। साक्षरता ने लोगों को न्याय व्यवस्था के विषय में बताया है। कहानी दहेज प्रथा को दिखाती नज़र आती है। किसी गरीब की बेटी को उसके पिता से अलग कर दिया गया। उस पिता से जिसने बेटी के सुख के लिए अपनी जमीन बेचकर उसका विवाह अच्छे परिवार में किया। कहानीकार ने यहाँ सामाजिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पढ़ी-लिखी और अनपढ़ दोनों ही प्रकार की नारी त्रासदी को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है।

संग्रह की बिंदी वाली, लुभावन व मैं मॉडर्न हूँ आदि कहानियां भी भिन्न-भिन्न रूपों में समाज में बेटी, मां, बहन व पत्नी यानी एक स्त्री की विभिन्न भूमिकाओं और उसकी स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करती हैं। तेरी पहचान नामक कहानी थर्ड जेंडर को लेकर लिखी गई है। एक तरफ इस विषय पर लोग बात तक नहीं करना चाहते। लेकिन लेखिका ने बड़े ही मनोयोग से इस कहानी के घटनाक्रम को लिखा है।

बिजेड़ी सरकार ने कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाया, हम सभी अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे: कनक बर्धन सिंहदेव

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: विधानसभा में दो राजा आमने-सामने हैं। एक हैं कनकवर्धन सिंह देव और दूसरे हैं रणेंद्र प्रताप स्वांई उर्फ राजा।विधानसभा में रणेंद्र प्रताप स्वैन ने पूछा, ₹जो सरकार खाद नहीं दे सकती, वह कोल्ड स्टोरेज कैसे दे सकती है?₹ जवाब में केवी सिंहदेव ने राजा स्वैन पर आरोप लगाया।विधानसभा में रणेंद्र प्रताप स्वैन ने पूछा, जो सरकार खाद नहीं दे सकती, वह कोल्ड स्टोरेज कैसे कर सकती है? जवाब में केवी सिंहदेव ने राजा स्वैन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, रणेंद्र प्रताप स्वैन ने खुद कृषि मंत्री रहते हुए कोल्ड स्टोरेज नहीं किया। जब हमारी सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की, तो वे सवाल उठा रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों को 2 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा खाद उपलब्ध कराई है। लेकिन एक बनावटी आंदोलन खड़ा कर दिया गया है। जहाँ भी खाद का आंदोलन चल रहा है, कितने विधायकों ने जाकर उसका जायज़ा लिया है। आपके समय में कोल्ड स्टोरेज नहीं हुआ। हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम सभी अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज करेंगे।

महिला कांग्रेस का विधानसभा घेरने का प्रयास

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: लोअर पीएमजी में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। महिला कांग्रेस नेता मीनाक्षी बहिनीपति के नेतृत्व में विधानसभा घेरने की कोशिश की जा रही है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नई सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, पिछले कुछ महीनों में राज्य में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं।कांग्रेस ने सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

मोहन सरकार ने महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को रोकने में सरकार की नाकामी के विरोध में महिला कांग्रेस ने विधानसभा घेरने का प्रयास किया है। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी तुलिकी कर्मा और कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुईं।

दिल्ली दंगे: झूठे गवाह, मनगढ़ंत सबूत

(आलेख : सवेरा, अनुवाद : संजय पराते)

इंडियन एक्सप्रेस (17 सितंबर 2025 को प्रकाशित) के एक विश्लेषण से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 2020 के घातक दिल्ली दंगों के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में, आरोपियों का लगभग पाँचवाँ हिस्सा बरी हो गया और उनके बरी होने का कारण मनगढ़ंत सबूत, काल्पनिक गवाह, पुलिस द्वारा लिखवाए गए बयान, जाँच अधिकारियों द्वारा जोड़े गए काल्पनिक 'तथ्य' और बनावटी बयान थे। न्यायाधीशों के इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, इस अखबार द्वारा विश्लेषित 93 मामलों में से 17 में आरोपित बरी हो गए। 2020 के दंगों से संबंधित कुल 695 मामले दिल्ली की निचली अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें से अगस्त 2025 के अंत तक 116 मामलों में फैसले सुनाए जा चुके हैं। इन 116 मामलों में से 97 में आरोपित बरी हो गए।

दिल्ली पुलिस, जिसे सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह नियंत्रित करते हैं, की बहुप्रशंसित लगन और प्रयासों से पहिया घूम चुका है। दंगों के कुछ ही हफ्ते बाद, 11 मार्च 2020 को, शाह ने संसद में एक लंबा बयान देकर दिल्ली पुलिस को उसके काम के लिए बधाई दी थी और बताया था कि 700 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 2647 लोगों को हिरासत में लिया गया/गिरफ्तार किया गया है, 25 कंप्यूटरों पर सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के सरकारी डेटाबेस से इस फुटेज का मिलान करके लोगों की पहचान करने के लिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए 40 टीमें काम कर रही हैं और 49 गंभीर मामलों की जांच के लिए दो विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जा रहा है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश थी और एक अलग मामला बनाकर उससे निपटा जाएगा।कुल मिलाकर, शाह ने एक आक्रामक और चतुर नेता की छवि पेश की, जिन्होंने उन हजारों परिवारों को न्याय दिलाने के लिए दर्जनों कर्मियों और नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिस नरसंहार में पीड़ित परिवारों के 53 लोग मारे गए थे और 700 घायल हो गए थे।

एक्सप्रेस की जाँच से कठोर सच्चाई उजागर होती है : कैसे ज़मीनी स्तर पर पुलिस अधिकारियों ने मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़कर ऐसे मामले बनाए, जिनका मक़सद अपराधियों को सज़ा दिलाना और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना था। और, ध्यान रहे, यह सब न सिर्फ़ सरकार के आकाओं को खुश करने के लिए किया गया, बल्कि उस सिद्धांत को भी पुष्ट करने के लिए किया गया, जो शाह ने ख़ुद उसी भाषण में संसद में पेश किया था। यह तथाकथित 'बड़ी साज़िश' का सिद्धांत था, जिसके अनुसार शहरी नक्सलियों और जेहादियों के एक समूह ने नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काने और गुमराह करने की साज़िश रची थी, जिससे राजधानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, और फिर चालाकी से इस उभार को व्यापक हिंसा में बदल दिया, ताकि सरकार की छवि ख़राब हो, खासकर जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शहर के दौरे पर आए थे। झूठे और मनगढ़ंत सबूत, पुलिस द्वारा लिखवाए गए बयान - सब कुछ - इस तथाकथित बड़ी साज़िश को साबित करने के लिए किया गया था।

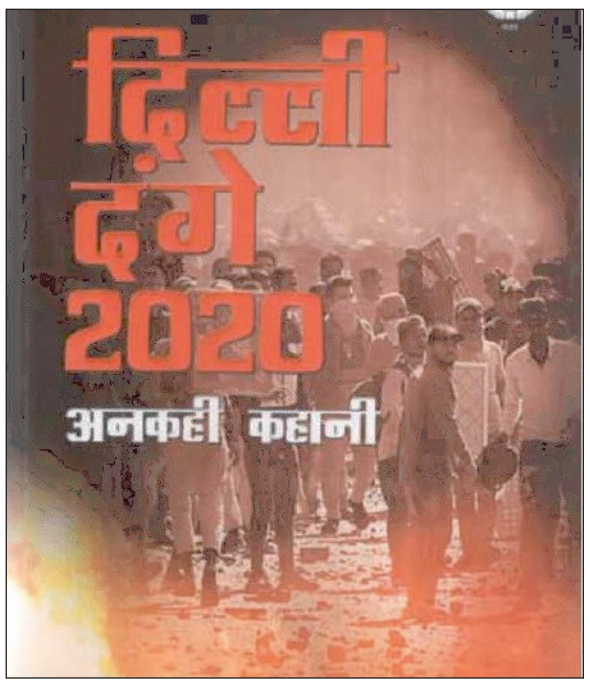

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अदालतों ने पाया कि पुलिस ने कम से कम 12 मामलों में या तो ₹कृत्रिम₹ गवाह पेश किए थे या ₹गढ़े हुए₹ सबूत पेश किए थे। कम से कम दो मामलों में, गवाहों ने गवाही दी कि पुलिस द्वारा उनके बताए जा रहे बयान वास्तव में उनके अपने नहीं थे, बल्कि ₹पुलिस द्वारा लिखवाए गए या उनमें हेरफेर किए गए₹ थे। एक मामले में, न्यायाधीश ने केस रिकॉर्ड में ₹हेरफेर₹ की ओर भी इशारा किया।

इंडियन एक्सप्रेस ने अगस्त में न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के ऐसे ही एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह द्वारा दिए गए आदेश को उद्धृत किया है : ₹जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्यों को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और इसके परिणामस्वरूप आरोपियों के अधिकारों का गंभीर हनन हुआ है, जिनके खिलाफ संभवतः केवल यह दिखाने के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया है कि मामला सुलझा लिया गया है... ऐसे मामलों से जांच प्रक्रिया और कानून के शासन में लोगों के विश्वास को गंभीर नुकसान पहुंचता है।₹

दो मामलों में, पुलिस ने झूठा दावा किया कि शिकायतकर्ता आरोपी नूर मोहम्मद की पहचान कर सकता है, लेकिन शिनाख्त परेड (टीआईपी) नहीं कराई गई, जिससे अदालत ने यह अनुमान लगाया कि पुलिस को अच्छी तरह पता था कि आरोपी के खिलाफ मामला मनगढ़ंत है। एक अन्य मामले में, अदालत ने अपने फैसले में कहा, ₹कथित अपराधों के प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद असलम नाम के किसी भी व्यक्ति का वास्तविक अस्तित्व भी संदेह के घेरे में आता है, और उसके काल्पनिक व्यक्ति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।₹

कुछ मामलों में, अभियोजन पक्ष ने स्वयं पुलिसकर्मियों को झूठे गवाह के रूप में पेश किया था, जैसा कि एक अन्य मामले के फैसले में बताया गया है, जिसमें न्यायाधीश ने लिखा : ₹इन परिस्थितियों में, यह संभव है कि अभियुक्त नूरा को दंगाइयों के बीच देखने का एक कृत्रिम दावा... पीडब्ल्यू (अभियोजन पक्ष के गवाह) 4 [कांस्टेबल रोहताश] द्वारा किया गया था।₹ कई तथाकथित झूठे गवाहों को पुलिस ने पेश किया और मुकदमों के दौरान उनका पर्दाफाश हुआ। जैसा कि एक फैसले में कहा गया है, ₹इन पुलिस गवाहों की गवाही में चूक की यह निरंतरता, उनके द्वारा दिए गए एकसार बयान की संभावना की ओर इशारा करती है... यह स्थिति (तीन) कथित चश्मदीद गवाहों द्वारा घटना के गवाह होने के कृत्रिम दावे की संभावना की ओर इशारा करती है...।₹ दो मामलों में, संबंधित न्यायाधीशों ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अभियोजन पक्ष के गवाहों को अभियुक्त की तस्वीरें दिखाने से यह आभास हुआ कि अभियोजन पक्ष के गवाह को "आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कृत्रिम रूप से चश्मदीद गवाह बनाया गया था।" एक अन्य मामले में, न्यायाधीश ने अपने फैसले में दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा केवल दो 'चश्मदीद गवाह' पेश किए गए थे और "दोनों ने ही आरोपी को दंगाइयों में से एक के रूप में पहचानने से इंकार किया है, और आगे कहा है कि शिकायत में दिए गए विवरण... ₹पुलिस के कहने पर उनके द्वारा लिखे गए थे।" न्यायाधीशों द्वारा गढ़े गए साक्ष्य के कई मामलों की ओर इशारा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ₹02.04.2020 को अभियुक्तों की पहचान संभवतः एक बाद के घटनाक्रम का परिणाम थी,₹ और एक अन्य जहां फैसले ने निष्कर्ष निकाला कि ₹...इन दो पीड़ितों/घायल अधिकारियों द्वारा अभियुक्तों की पहचान की प्रक्रिया संदेह के बादलों से घिरी हुई है...₹ एक अन्य मामले में, न्यायाधीश ने कहा कि ₹...(एक गवाह के) बयान के संबंध में केस डायरी में संभावित हेरफेर है।₹

पहले भी मार्च 2020 (दंगों के कुछ हफ़्ते बाद) में मीडिया रिपोर्टों में दर्ज मामलों में हेराफेरी करके लोगों को झूठे एफ़आईआर में फँसाने के कई मामले रिपोर्ट किए गए थे। उदाहरण के लिए, यह बताया गया था कि पूर्वी दिल्ली के दयालपुर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत दर्ज एफ़आईआर संख्या 0066/2020, 0067/2020, 0068/2020, 0069/2020 और 0070/2020 में, कहानी बहुत मिलती-जुलती है, बस फ़र्क़ शिकायतकर्ता के नाम और उस जगह की है, जहाँ पुलिस ने आरोपी को देखने का दावा किया था। इन सभी एफआईआर में कहा गया है कि अमुक कांस्टेबल को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिसने पुलिस से बचने की कोशिश की, उसे रोका गया और उसकी तलाशी ली गई, उसके पास एक देसी पिस्तौल मिली और उसे हिरासत में ले लिया गया। ये सभी आरोपी मुसलमान थे। इस मीडिया रिपोर्ट में आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील के हवाले से कहा गया, ₹दयालपुर थाने के पास दो चौराहों पर पथराव की घटना हो रही थी। दंगाई भीड़ के बीच फंसे लोग किसी तरह थाने में शरण लेने के लिए घुस गए। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के बजाय, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, प्रताड़ित किया और बाद में गिरफ्तार कर लिया।₹ बाद में पुलिस अधिकारियों ने इन खबरों का खंडन किया।

दंगों के बाद मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई एक और आम घटना यह थी कि एक समुदाय के कुछ लोगों को बचाने और दूसरे समुदाय की शिकायतों को कमजोर करने के लिए एफआईआर को एक साथ जोड़ा जा रहा था। नवंबर 2023 में, दिल्ली की एक अदालत ने असंबंधित शिकायतों को गलत तरीके से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की निंदा की। संबंधित शिकायतों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, खासकर सामूहिक हिंसा की घटनाओं में, जबकि दिल्ली में कई मामलों में जो हुआ, वह स्पष्ट रूप से अवैध और दुर्भावनापूर्ण था।

एक गंभीर मामले में, हाजी हासिम अली ने करावल नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 फरवरी को शिव विहार में उनके दो मंजिला घर को एक सशस्त्र भीड़ ने आग लगा दी थी। उनकी शिकायत को नरेश चंद द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 72/2020 के साथ मिला दिया गया। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि उनके घर और दुकान को दंगाई भीड़ ने जला दिया था। यहां तक कि अदालत ने भी जांच के दौरान दिल्ली पुलिस के ₹कठोर रवैये₹ के लिए उसे कड़ी फटकार लगाई थी और पुलिस की कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने 26 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए कहा था, ₹यह वास्तव में अजीब है कि प्रतिवादी नंबर 1 (अली) के घर को जलाने के संबंध में शिकायत को नरेश चंद की शिकायत के साथ जोड़ दिया गया, जो कि एफआईआर नंबर 72/2020, पीएस करावल नगर है और बाद में प्रतिवादी नंबर 1 को उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका अर्थ है कि वह न केवल मामले में शिकायतकर्ता है, बल्कि एक आरोपी भी है, जो एक स्पष्ट मूर्खता है।₹

दिल्ली दंगों की यह दुखद घटना, सत्ताधारी दल द्वारा अपनी ज़हरीली और विभाजनकारी विचारधारा को साधने के लिए जाँच एजेंसियों के अपहरण को एक बार फिर उजागर करती है। लेकिन यह अपहरण न्याय प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को ढकने की कोशिश करती है और क़ानून के शासन को तहस-नहस करती है। सौभाग्य से, न्यायिक जाँच कुछ मामलों में इस ख़तरनाक चाल को पकड़ पाने में कामयाब रही है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और राजनैतिक टिप्पणीकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।

अब मतदाता सोशल मीडिया के ज़रिए ले सकेंगे चुनाव विभाग से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी

क्यूआर कोड स्कैन करें और जुड़ें मुख्य निर्वाचन कार्यालय पंजाब के सोशल मीडिया से

अमृतसर, 24 सितंबर (साहिल बेरी)

चुनाव से संबंधित हर तरह की सही, सटीक और समय पर जानकारी आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय पंजाब की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती साक्षी साहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर उपलब्ध मुख्य निर्वाचन कार्यालय के आधिकारिक अकाउंट से जुड़ सकते हैं और चुनाव से जुड़ी हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके इन अकाउंट्स को फॉलो किया जा सकता है और चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनतम अपडेट्स और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता से सीधा संपर्क बनाने और उन्हें हर आवश्यक जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया सबसे प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है।

इसीलिए अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया हैंडल को सक्रिय और कारगर बनाया गया है। यह लोगों को सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, नागरिकों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़कर इसका लाभ उठाएं।

नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे : करमजीत सिंह रिंटू:88 फुट मेन रोड के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया

सड़कों को बनवाने के लोगों से किए गए वादों को पूरा किया जा रहा

अमृतसर, 24 सितंबर (साहिल बेरी)

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन एवं नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज कर्मजीत सिंह रिंटू ने कहा कि लोगों से किए गए टूटी हुई सड़कों को बनवाने के वादों को पूरा किया जा रहा है। करमजीत सिंह रिंटू ने 88 फुट मेन रोड के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 महीनो के भीतर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र की सभी टूटी हुई सड़कों को बनवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों को बनवाने के विकास कार्यों की नगर निगम, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और पीडब्लयूडी से पहले से ही मंजूरी ले ली गई है।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को सभी तरह की सुविधा दे रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब के हर परिवार को ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करके एक बड़ा फ़ैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी की यह घोषणा पंजाब को स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने की पंजाब सरकार द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रियंका शर्मा, रितेश शर्मा, गुलजार सिंह बिट्टू, अनेक सिंह,विशाखा सिंह, बलविंदर काला, साहिल सगर, अजय गिल, बॉबी सरीन, कुलदीप लड्डू और भारी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे।

जिला प्रशासन निर्देश पर सरायकेला डीएमो ने 500 सी एफ टी बालू ,एक निकासी नाव किया जप्त

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला, सरायकेला उपायुक्त के निदेशानुसार जिला खनन विभाग, संबंधित थाना के पुलिस बल के साथ राजनगर थाना अंतर्गत डुमरडीहा पंचायत स्थित छेलकानी एवं कोलाबेडिया नदी घाट का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के क्रम में उक्त घाटों पर किसी भी व्यक्ति अथवा वाहन द्वारा अवैध बालू उत्खनन करते हुए नहीं पाया गया। तथापि, घाटों पर अवैध उत्खनन हेतु प्रयुक्त डोंगी नाव (प्लेटफार्म) पाई गई। प्रशासन की सख़्ती के तहत पुलिस बल एवं स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से

सभी डोंगी नावों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

इसी क्रम में अंचल अधिकारी इचागढ़ दीपक कुमार द्वारा इचागढ़ क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसी भी वाहन को अवैध खनन करते हुए नहीं पाया गया, तथापि लगभग 5000 सी एफ टी . की अवैध बालू का स्टॉक पाया गया, जिस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त कार्रवाई जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी की उपस्थिति में की गई तथा जिले में अवैध बालू उत्खनन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

राहत पैकेज दिलवाने की बजाय उल्टा पीड़ितों की लाशों पर सियासी रोटियाँ सेंकने वालों का चेहरा जल्द ही बेनकाब होगा – धालीवाल

* कल यानी 26 से 29 सितंबर तक होने वाले विधानसभा सत्र में बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा होगी – धालीवाल
* धालीवाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सफाई मुहिम का अंतिम पड़ाव रमदास में पूरा किया –

अमृतसर/अजनाला, (साहिल बेरी)

हलका विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए 20 हज़ार करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज केंद्र से दिलवाने और पंजाब के केंद्र पर बकाया 8 हज़ार करोड़ रुपये ग्रामीण विकास फंड समेत 50 हज़ार करोड़ रुपये जीएसटी राहत फंड के लिए मोदी सरकार से आवाज़ बुलंद करने की बजाय, बाढ़ पीड़ितों की दिन-रात सेवा में जुटी मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के उल्टा 12 हज़ार करोड़ रुपये एसडीआरएफ फंड की आड़ में बाढ़ पीड़ितों की लाशों, बर्बाद फसलों, उजड़े घरों, बह गए पशुओं और तहस-नहस सरकारी ढाँचे को अनदेखा कर राजनीतिक रोटियाँ सेंकने और राहत कार्यों से ध्यान भटकाने वाली कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल आदि विरोधी पार्टियों का बाढ़ पीड़ित विरोधी चेहरा तथ्यों पर आधारित जन बहस के दौरान जल्द ही उजागर होगा।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा बाढ़ पर 26 से 29 सितंबर तक मान सरकार द्वारा बुलाई गई पंजाब विधानसभा की विशेष बैठक में गहन चर्चा हो सकती है।

श्री धालीवाल आज हलके में सफाई अभियान के अंतिम पड़ाव के दौरान बाढ़ प्रभावित ऐतिहासिक नगर *रमदास* में ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्म ज्ञानी समाध बाबा बुढ़ा साहिब मार्ग की सफाई कार्य पूरा करने और रमदास कस्बे के वार्ड नं. 4 में बाढ़ प्रभावित झुग्गी-झोपड़ी वासियों समेत ज़रूरतमंदों में *योग और सेवा परिवार (रजिः)* के सहयोग से 30-30 फोल्डिंग बेड, कंबल, लोइयाँ और टॉर्च (बैटरी) बाँटने के उपरांत चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित सभी वर्गों के पुनर्वास के तहत जनजीवन को ऊपर उठाने के लिए भगवंत मान सरकार वचनबद्ध है, परंतु अन्नदाता (किसानों) की उन ज़मीनों में, जो पहाड़ों से आई बाढ़ के पानी के साथ दरियाओं में बहकर आए पत्थरों का मलबा, लाल मिट्टी, रेत और गाद से दब चुकी हैं, अगली रबी की फसल की बुआई पंजाब सरकार किसानों के साथ मिलकर एक चुनौती के रूप में ले रही है।

उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण उपजाऊ मिट्टी बहकर दरियाओं में चली जाने और गाद, मलबे, रेत से भरे खेतों की सफाई कर उन्हें खेती योग्य बनाने के बाद भी उपजाऊ ज़मीन में *नाइट्रोजन और जिंक जैसे पोषक तत्वों* की भारी कमी हो जाती है। इसी कारण खेती योग्य बने खेतों में खेती विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा प्रमाणित गेहूँ के बीज को सरकारी स्तर पर और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से उपलब्ध करवाने की बाकायदा योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने जानकारी दी कि पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत लुधियाना विश्वविद्यालय द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों का सर्वे किया जा रहा है, ताकि समय पर किसानों को गेहूँ समेत अन्य रबी की फसलों और सब्ज़ियों के बीज उपलब्ध कराए जा सकें।

इस मौके पर खुशपाल सिंह धालीवाल, अमनदीप कौर धालीवाल, पीए मुख्तार सिंह बलड़वाल, चेयरमैन बब्बू चेतनपुरा, शहरी प्रधान हरपाल सिंह रमदास, काबिल सिंह पछिया, *योग और सेवा परिवार संस्था* के पैटर्न विनोद डावर, मुख्य सलाहकार कप्पल चुग, राजकुमार कपूर, एन.के.एच. इंडस्ट्रीज़ के मालिक आदि मौजूद थे।

झारखंड माटी की बालीवुड गायिका शिल्पा राव मिली मुख्यमंत्री हेमंत व पत्नी कल्पना से

श्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका सम्मान राज्य का सम्मान है : हेमंत सोरेन

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन से बुधवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड के जमशेदपुर की बेटी एवं बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका का

पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर शिल्पा राव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई मौकों पर हमारी बेटियों ने राष्ट्रीय फलक पर राज्य का नाम रोशन किया है। आपकी यह सफलता झारखंड की युवा पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री ने शिल्पा राव से कहा कि आपको मिला यह सम्मान राज्य का भी सम्मान है। मुख्यमंत्री ने बॉलीवुड सिंगर श्रीमती शिल्पा राव को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की।

मौके परम बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने गायिकी जीवन की शुरुआत से लेकर बॉलीवुड सिंगर के रूप में नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित होने की यात्रा के अनुभव साझा किए।

पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने की असहाय व्यक्ति की मदद

बदायूं। जवाहरपुरी सुनीति पेट्रोल पम्प पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने गए पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने एक व्यक्ति को वहाँ लेटा देखा, जिसके सर में कीड़े पड़े हुए थे, विकेंद्र शर्मा ने तुरंत 112 पुलिस को सूचना दी और 108 पर एम्बुलेंस के लिए सूचना दी, मौके पर 112 पुलिस आयी परन्तु एम्बुलेंस नहीं आयी, थाना सिविल लाइन की जवाहर पुरी चौकी पुलिस ने भी मौके पर आकर एम्बुलेंस के लिए सम्पर्क किया, परन्तु 1 घंटे तक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी, पुलिस और पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा के काफ़ी प्रयासों के बाद एम्बुलेंस मौके पर आयी और व्यक्ति को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले गई, अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आयी, कोई भी उस सडे हुए व्यक्ति को हाथ लगाने को तैयार नहीं, पुलिस ने उसे उतरवाकर अंदर वार्ड तक पहुंचवाया। विकेंद्र शर्मा ने कहा जहाँ हम एक बेजुवान को सड़ी हालत में सडक पर नहीं छोड सकते ये तो फिर भी इंसान है इसे कैसे छोड़ सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023